मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक

वर्ष: 43 अंक: 20 नई दिल्ली (कुल पेज 16) 14 – 20 मई 2023 मूल्य 7 रुपये

अंदर के पेजों में

मोदी सरकार से प्रेस की आजादी को खतरा.....3

जारी है भाकपा का देशव्यापी जन जागरण अभियान.....8–9

अमर्त्य सेन का उत्पीड़न.....11

भारत और जी20

बड़बोलापन और वास्तविकता

डी. राजा

बीस देशों के समूह, जिसे जी20 कहा जाता है, की अध्यक्षता इस साल बड़े गाजे–बाजे के साथ भारत कर रहा है। जी20 का गठन भूमंडलीय अर्थव्यवस्था से संबंधित व्यापकतर मुद्दों को डील करने के लिए 1999 में किया गया था। इसका गठन उस समय किया गया था जब नव उदारवाद विश्व भर में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था परंतु वह समूह आर्थिक रुझानों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सका और 2008 के वित्तीय संकट को नहीं टाल सका। तत्पश्चात, जब वह उथल–पुथल भरे दिनों में नीतियों पर प्रभाव डालने लगे तो जी8/जी7 ग्रुप और अधिक महत्वपूर्ण बन गए। जब इन्हीं अत्यंत सीमित ग्रुपिंगों पर बहिष्करण के आरोप लगे, जी20 ग्रुप एक बार फिर ऐसा मंच बन गया जो प्रत्यक्षतः समावेशी था यद्यपि वह संयुक्त राष्ट्र की तुलना में काफी सीमित था। जी20 की भारत की अध्यक्षता के घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों निहितार्थ हैं और हमें इन दोनों के संबंध में देखना चाहिए कि अपने देश के और विदेशों के लोगों को इससे कितना फायदा पहुंचेगा।

जी20 की अध्यक्षता विभिन्न देशों को बारी–बारी से मिलती है। इस लिहाज से यह एक सामान्य प्रक्रिया है। परंतु भाजपा और भारत का मीडिया इसे एक बड़ी घटना के तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बढ़ते प्रभाव के सबूत के रूप में उछाल रहा है। लोगों को यह मिथक बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तिगत करिश्मा एवं प्रभाव भारत के पक्ष में डिप्लोमैटिक ज्वार भाटे में बदल रहा है। तथ्य मात्र यह है कि जी 20 की अध्यक्षता बारी–बारी से मिलती रहती है और इस बार भारत को मिली है। यह स्वयं भारत के लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। इस मामले में प्रधानमंत्री की कोई उपलब्धि है तो केवल इतनी कि भारत को यह अध्यक्षता 2022 में मिल रही थी परंतु उन्होंने इसे 1साल टालकर 2023 के लिए करा दिया, ठीक उस समय के लिए जब कि नौ राज्यों में विधान सभा के चुनाव और केवल कुछ ही महीने बाद 2024 के आम चुनाव होंगे।

मंसूबा यह है कि जी20 की विभिन्न मीटिंगों के लिए विदेशी प्रतिनिधि आएंगे, देश भर में वे जाएंगे और हर कहीं प्रधानमंत्री द्वारा अभिनन्दन के बड़े–बड़े बोर्डिंग लगेंगे और यह कार्यक्रम भाजपा के लिए चुनावी स्प्रिंग बोर्ड का काम करेंगे और सारा खर्चा सरकारी खजाने से होगा। जी20 की अध्यक्षता के एजेंडे के संबंध में प्रधानमंत्री ने एक ब्लॉग–पोस्ट में विस्तारपूर्वक बताया। इस मामले में लफ्फाजी और असलियत के बीच फर्क अत्यंत स्पष्ट है। उनके शब्द थे ''भाषाओं, धर्मो, रीति–रिवाजों और विश्वासों की भारी विविधता'' के साथ ''भारत दुनिया एक लघु ब्रह्मांड है''।

आरएसएस–भाजपा एकरूपता (होमोजेनिटी) की सनक से ग्रस्त हैं और वे सक्रिय होकर विविधता एवं अंतरों को मिटाने की कोशिश करते रहते हैं। हिन्दी थोपने का मामला हो या धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने का, लोग क्या खाते हैं उसके लिए उन्हें पीट–पीट कर मार डालने का मामला हो या वे किस तरह के कपड़े पहनते हैं उसके लिए लोगों को निशाने पर लेने का–एकरूपता का आरएसएस का विचार हमेशा सक्रिय रहता है। देश के संघीय ढांचे का विघटन मोदी सरकार का एक सतत् लक्ष्य रहा है। आगे जबकि भारत के लोकतांत्रिक चरित्र पर बहुसंख्यकीय आक्रमण द्वारा धावा बोला जा रहा है, प्रधानमंत्री ने लिखा, ''भारत लोकतंत्र के बुनियादी डीएनए को योगदान देता है''।

आज संसद को व्यर्थ एवं अनावश्यक बनाया जा रहा है और न्याय पालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण किया जा रहा है। विपक्ष के विरूद्ध केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और संचार माध्यमों को इसकी अनदेखी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। विरोध/असहमति को अपराध की संज्ञा दी जा रही है। नागरिक स्वतंत्रता का गला घोटा जा रहा है। जो कोई भी सरकार पर सवाल उठाए, उसे बेनकाब करे, उसके खिलाफ नंशृसतापूर्ण कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन ने जिन बुनियादी धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं आलोचनात्मक मूल्यों को आगे बढ़ाया था उन सब पर आज खतरा है। अडानी जैसे कारपोरेटें और वित्तपूंजी की भूमिका के संबंध में महत्वपूर्ण सवालों को संसद में नहीं उठाने दिया गया। यह गलाघोटू स्थिति ''लोकतंत्र के बुनियादी डीएनए'' के लिए एक चिंताजनक बात है और इससे लफ्फाजी और असलियत के बीव बहुत बड़े अंतर का पता चलता है।

प्रधानमंत्री ने जी20 शिखर बैठक के लिए ''एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य'' का मंत्र दिया। मोदी प्रशासन का मूल्यांकन करने के लिए यह नारा भी अच्छा पैमाना है। एक परिवार में इसके सदस्यों के बीच भेदभाव नहीं किया जाता। परंतु मोदी के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव एक संस्थात्मक बात बन गया है। विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) कानून जनता के एक हिस्से के साथ उनके धर्म के आधार पर खुलेआम भेदभाव करता है। नागरिकता (संशोधन) कानून मोदी सरकार की विदेश नीति के लिए एक इम्तिहान भी था क्योंकि इस भेदभाव करने वाले कानून से भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छिछालेदार हुई और इस कानून के बाद दिल्ली दंगे हुए।

आरएसएस के एक पूर्व प्रमुख एम. एस. गोलवलकर ने स्वतंत्रता और देश के विभाजन से पहले ही कहा था कि अल्पसंख्यक देश में रह सकते हैं परंतु वे मातहती के साथ रहेंगे, किसी बात का भी दावा नहीं करेंगे, उन्हें कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, उन्हें किसी किस्म का तरजीही सलूक नहीं मिलेगा और उन्हें नागरिक का अधिकार भी नहीं मिलेगा।

यही वह फूट परस्त और सांप्रदायिक बुनियाद है जिस पर आरएसएस भाजपा आज देश में ''परिवार'' का निर्माण करने की कोशिश कर रही है। आरएसएस–भाजपा शासन के अंतर्गत, सांप्रदायिक, जातिवादी, नारीद्वेषी तत्वों के हौसले बढ़ गए हैं और वे एकिक, धर्मतांत्रिक और श्रेणीबद्ध हिन्दू राष्ट्र बनाने के अपने भावी लक्ष्य की दिशा काम कर रहे हैं। वह भविष्य किस तरह का नजर आएगा इसका अनुमान करना कठिन नहीं। भारत ने जब गुटनिरपेक्षता का दृष्टिकोण अपनाया तो दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। परंतु, पिछले कुछ वर्षो में, अमरीका के नेतृत्व में पश्चिमी ग्रुप के साथ भारत की बढ़ती निकटता ने हमारे लिए अनेक समस्याएं खड़ी कर दी हैं और हम देख सकते है कि भूमंडलीय दक्षिण में हमारी जो परंपरागत साख रही है उसका क्षरण हुआ है।

जी20 की अध्यक्षता प्राप्त करने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने एक सर्वदलीय मीटिंग की अध्यक्षता की। उस मीटिंग में भूमंडलीय दक्षिण और भूमंडलीय वित्त संस्थानों में सुधार करने एवं उनकी पुनःउन्मुखता के संबंध में उल्लेख किया गया। परंतु जी20 के अध्यक्ष के तौर पर उसका भारत के लिए क्या अर्थ होगा, इसके संबंध में कोई संकेत नहीं थे। तथापि बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) के संबंध में जी20 विशेषज्ञ समिति से कुछ संकेत मिल रहे हैं। समिति अपनी रिपोर्ट में कुछ कदमों की सिफारिश करेगी जो महत्वपूर्ण फर्क ला सकते है। इनमें निजी पूंजी जुटाने के लिए नए तंत्र और विशेष निवेश एवं व्यय प्राथमिकताएं शामिल हैं (विश्व बैंक ग्रुप 2023 का क्रम विकास)। समिति की सिफारिशों के संबंध में संभवतः अनेक लोगों को संशय भी हो।

हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता, जिन्हें आवश्यकता है उनके लिए, एकजुटता एवं समर्थन जुटाने और बढ़ाने के संबंध में अत्यंत सतर्क थे। स्वतंत्रता के बाद, उत्पीड़ितों की एकता की इस विरासत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के तौर पर एक संस्थागत रूप ले लिया और भारत उपनिवेशवाद के खात्मे, अफ्रीकी–एशियाई एकता और शांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवाज बनकर उभरा। आज भारत पश्चिम के साथ निकटता बढ़ा रहा है और अमरीकी नेतृत्व में सैन्य गठबंधनों की तरफ भारत को खींचा जा रहा है। इससे भारत की साख खत्म होती जा रही है। इस नीति का परिणाम यह होता है कि भारत महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक पोजीशन लेने में विफल रहता है और पश्चिमी दादागिरी के खिलाफ भूमंडलीय दक्षिण देशों के बीच एकता नहीं बन पाती।

पिछले कुछ वर्षो में भारत की विदेश नीति–प्राथमिकताएं संकीर्ण हो गई हैं। सहयोग, एकजुटता, शांति एवं प्रगति की नीति का अनुसरण करने के बजाय हमारे डिप्लोमैटिक कामों में लगे लोगों की शक्ति केवल एक नेता की छवि बनाने और प्रचारित करने में लगी रहती है। यह शोचनीय है कि जब अन्य देशों की विदेश नीतियां ठोस उपलब्धियों पर फोकस करती हैं, हमारा विदेशी नीति–विमर्श स्वतंत्र विदेश नीति पर विचार करने पर फोकस नहीं करता।

प्रधानमंत्री का एक प्रिय वाक्यांश है–वसुधैव कुटुम्बकम। इसमें भाईचारे का संदेश है। इसमें समूचे विश्व को एक परिवार समझा गया है। एक अन्य सूक्ति है–यह मेरा है, और यह पराया है, इस तरह की सोच केवल संकीर्ण मन वाले लोग ही रखते हैं। जी20 की अध्यक्षता हमारी सरकार के लिए एक अवसर है कि वह यह दिखाए कि वह उदारता में समर्थ है और लोगों के साथ समान बर्ताव करे जैसाकि एक परिवार में किया जाता है। भूमंडलीय दक्षिण का एक बड़ा परिवार इसकी प्रतीक्षा करता है। यह हमारा दायित्व है कि हम अपने देश में भी और विदेश में भी ''वसुधैव कुटुम्बकम'' के तरीके से काम और व्यवहार करें।

मणिपुर ने दिखाया भाजपा का असली चेहरा

संपादकीय

मणिपुर, भाजपा के लिए एक तुरूप के पत्ते के जैसे था। 2017 में उन्होंने पहली बार वहाँ सत्ता में आने के बाद से सुनियोजित योजना के साथ मणिपुर को उत्तर–पूर्व के लिए छलांग मारने के तख्ते के जैसे देखा। राज्य में भाजपा को सत्ता की प्राप्ति कुटिल तरीकों से हुई थी। 60 सदस्यीय विधानसभा में भाकपा के केवल 21 विधायक थे, जबकि कांग्रेस के 28 विधायक थे। विधायकों की खरीद–फरोख्त और राज्यपाल कार्यालय की छल–कपट ने भाजपा को मणिपुर में अपने पैर रखने में मदद की। वहाँ से उन्होंने नफरत के शिकंजे को एक के बाद एक पड़ोसी राज्यों में फैलाना शुरू कर दिया। उनकी झूठ की फैक्टरी में एक नई कहानी पकाई गई कि धार्मिक अल्पसंख्यक और जनजातीय आबादी भाजपा के कट्टर समर्थक बन गए हैं। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक इस गढ़ी गई कहानी को 'स्टॉर्म ट्रूपर्स' द्वारा फैलाया गया। अब इस कहानी के टुकड़े–टुकड़े हो गए हैं। इस राज्य को संकट में डाल दिया गया है और अल्पसंख्यकों, जनजातियों और समाज के अन्य वर्गों के संबंध में भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया है। पूर्वोत्तर के लोगों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण दिनों के दौरान, भारत ने देश के प्रधानमंत्री को दक्षिणी राज्य कर्नाटक में वोट के लिए हल चलाते हुए देखा।

पूरे मणिपुर राज्य में हिंसा का कारण एक उच्च न्यायालय का आदेश था जिसने राज्य सरकार को मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए एक सिफारिश दाखिल करने का निर्देश दिया था। राज्य की आदिवासी आबादी ने इसका विरोध किया और तुरन्त ही, हिंसक झड़पों, आगजनी और गुस्से ने पूरे राज्य को घेर लिया। उच्च न्यायालय के निर्देश से शायद हिंसा उत्प्रेरित हुई होगी लेकिन यह स्पष्ट है कि लोगों को कई लेबलों में विभाजित करने और एक को दूसरे के खिलाफ रखने की भाजपा नीति राज्य में अशांति के लिए जिम्मेदार है। भाजपा की सत्ता को केंद्रीकृत करने और हितधारकों के साथ बातचीत नहीं करने की प्रवृत्ति ने राज्य को हिंसा के इस गर्त में धकेल दिया है, जिसने 60 से अधिक लोगों की जानें ली हैं और हजारों बेघर हो गए हैं। लोगों को विभाजित करने से भाजपा को चुनावी रूप से अच्छे नतीजे मिले लेकिन समाज में विभाजन के विनाशकारी परिणाम दीर्घकालिक हैं और भाजपा को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। सत्ता पर कब्जा करने की उनकी भूख ने न केवल मणिपुर को बल्कि पूरे पूर्वोत्तर को वि त कर दिया है। भाजपा ने इस अशांति से कुछ भी नहीं सीखा। जब मणिपुर के लोगों की आँखों में आँसू थे, तब पूरा भाजपा नेतृत्व कर्नाटक पर मंडरा रहा था, वहाँ वे वही कर रहे थे जो करते हैं; लोगों को विभाजित करना। भाजपा जो नफरत और विभाजन के बीज बो रही है हमारी इस मिट्टी के लिए जहरीले हैं जो कि समाज के सभी वर्गों के बलिदान से समृद्ध है।

मणिपुर में सामान्य स्थिति और स्थायी शांति की बहाली देश और सरकार के सामने आज सबसे बड़ा काम है। हालांकि, संबंधित मुद्दों के बारे में भाजपा की संकीर्ण समझ के कारण समझ बनी है कि यह केवल कानून–व्यवस्था का मुद्दा है। सशस्त्र बलों की भारी तैनाती से हिंसा के मूल कारणों का समाधान नहीं होगा। सरकार के साथ गहरी निराशा के परिणामस्वरूप हिंसा हो रही है और इसका समाधान राजनीतिक और सामाजिक रूप से किया जाना चाहिए। सभी हितधारकों को उनके प्रतिनिधि संगठनों और राजनीतिक दलों से परामर्श करके विश्वास में लिया जाना चाहिए और भाकपा ने केंद्र सरकार से इसकी मांग की थी। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में डालने की सिफारिश करने वाले उच्च न्यायालय के निर्देश के मामले पर बातचीत करने की सहमति व्यक्त की है। सलाह–मशविरा को हिंसा के तत्काल उत्प्रेरकों के परे होना चाहिए और दीर्घकालिक सामाजिक स्थिरता के मद्देनजर मुद्दों का समाधान करना चाहिए। कैसे और क्यों घृणा ने मणिपुर में एक प्रजनन स्थल पाया है, इसकी जांच की जानी चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार ताकतों को उजागर किया जाना चाहिए। विस्थापितों के तत्काल पुनर्वास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हिंसा में जान गंवाने वालों और घायल लोगों के लिए पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

देश को तेजी से दिखाई दे रहा है कि भाजपा–आरएसएस अपने वैचारिक प्रवृति से ही देश पर शासन करने के अयोग्य है। भाजपा–आरएसएस ने चुनावी फायदे के लिए समाज में दरार पैदा की है और यह समाज के लिए विनाशकारी है। भारत जैसे विविधता वाले देश को, खासकर कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, संवाद के बिना नहीं चलाया जा सकता, लेकिन भाजपा–आरएसएस वैचारिक रूप से भारी केंद्रीकृत और असीम शक्ति के पक्ष में हैं। इस वैचारिक डिजाइन से देश में शांति और सद्भाव के लिए संकट पैदा हो रहा है। इस वैचारिक विन्यास के कारण देश में शांति और एकता विपत्ति में है। भाजपा के शासन में असंतोष व्यापक है और जो लोग इस आसान असंतोष के लिए जिम्मेदार हैं, उनके पास लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए समय या धैर्य कम है, वे निरंतर चुनाव मोड में हैं। भाजपा की कश्मीर नीति की घोर विफलता के बाद अब हम पूर्वोत्तर में इस घटना को दोहराते हुए देख रहे हैं। स्थिति के और खराब होने से पहले, शांति स्थापना को प्राथमिकता देनी होगी और संयुक्त प्रयासों के माध्यम से लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना होगा। लोगों तक पहुंचना होगा और उन्हें हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्ष लोकाचार और स्वतंत्रता आंदोलन की समावेशी विरासत से अवगत कराना होगा। आरएसएस–भाजपा का शासन हमारे देशवासियों के बीच पैदा की गई नफरत पर आधारित है। इस घृणा को परास्त किया जाना चाहिए और इसके स्थान पर प्रेम, करुणा और सहानुभूति होनी चाहिए जिससे हमारा देश शांति, प्रगति और समृद्धि के युग में प्रवेश हो सके।

पाकिस्तानी जासूस के संघी संबंधों को छुपा रहे मीड़िया और सरकार

पुणे में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के निदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर इस समय चर्चा में हैं। आरोप है कि कुरूलकर हनीट्रैप में फंस गए और रक्षा क्षेत्र की गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान को मुहैया कराई। इस मामले में आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने उसे गिरफ्तार किया है। खुफिया एजेंसी (रिसर्च एंड एनालिसिस विंग–रॉ) कुरूलकर से पूछताछ कर रही है। प्रदीप कुरूलकर पुणे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में देशभक्ति का पाठ पढ़ने वाले राष्ट्रवादी संघ हैं। जिसे भाजपा और संघ सहित भाजपा का ब्राहमणवादी मीड़िया नहीं दिखा रहा है। हालांकि ऐसी राष्ट्रवादी शिक्षा देने का संघ का लंबा और पुराना इतिहास रहा है। पाकिस्तान को देश के रक्षा क्षेत्र की जानकारी मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किए गए प्रदीप कुरुलकर ने पिछले साल यूट्यूब चैनल नूमाविया को इंटरव्यू दिया। इसमें उनकी पत्नी और बेटे ने भी हिस्सा लिया था। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने संघी शाखा में गुजारे अपने दिनों की गर्व के साथ

चर्चा की थी।

परंपरावादी संघी था जासूस

पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले कुरुलकर अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरा बेटा अब संघकार्य में जाता है और कि यह हमारी चौथी पीढ़ी है। मेरे दादाजी शाखा में ही जाया करते थे। उन्होंने एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया। वे बहुत अच्छे गणितज्ञ थे। चूंकि उनके खाते पक्के थे, इसलिए उन्हें बैंक और शाखा के नोट्स रखने का काम था। वह काम बाद में उनके पिता के पास आया। कुरुलकर इस साक्षात्कार में यह भी कहते हैं कि वे गणित और विज्ञान के शिक्षक थे।

उसने यह भी स्वीकार किया कि वह पांच साल की उम्र से ही शाखा जा रहा है। कुरुलकर कहते हैं, उस समय, मुझे सड़क पार करते समय मदद की आवश्यकता होती थी, कोई मुझे ले जाता था, फिर जब से मैंने स्वतंत्र रूप से सड़क पार करना शुरू किया, यह शाम को मेरी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग था। कई वर्षों तक मेरे संघ शिक्षा वर्ग में रहने के बाद प्रचारकों की एक सभा होती थी, जिसे बाबाराव भिडे ने शुरू किया था। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ वर्षों तक मैंने उनके बुद्धिजीवियों के नोट लेने का भी काम किया है।

कामरेड रामटहल पूर्वे के हत्यारे को फांसी की सजा दो

पटना: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने मधुबनी जिला के वरिष्ठ नेता व पार्टी के कलुआही अंचल के सचिव रामटहल पूर्वे की जघन्य हत्या पर गहरी चिंता जताते हुए अपनी शोक संवेदना प्रेषित की है। उन्होंने राज्य में बढ़ रहे अपराध की पृष्ठभूमि को ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए राज्य सरकार से कामरेड रामटहल पूर्वे के हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और स्पीडी ट्रायल चलाकर हत्यारे को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। हत्या का ब्यौरा देते हुए भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा 85 वर्षीय कामरेड रामटहल पूर्वे की हत्या कर उनके चेहरे पर तेजाब डालकर पहचान को नष्ट करने की मंशा से शव को कलुआही थाने के पुरसोलियां गांव की जंगल वाली गाछी में फेंक दिया गया। शहीद कामरेड रामटहल पूर्वे हर दिन की भांति 5 मई 2023 को घर से खाना खाकर पार्टी कार्य से निकले लेकिन घर नहीं लौटे। जब तीन दिनों तक कामरेड घर नहीं लौटे तो उनकी पुत्र–वधू ने पार्टी के मधुबनी जिला सचिव कामरेड मिथिलेश झा को 7 मई 2023 को सूचना दी। इसके बाद उनकी खोज खबर शुरू हुई और उनकी लाश 8 मई को पुरसौलिया गावँ के उक्त बगीचा में फेंकी हुई मिली। उनका अंतिम संस्कार 8 मई को उनके पैतृक गांव पुरसौलिया में कर दिया गया जिसमें पार्टी के राज्य सचिव कामरेड रामनरेश पाण्डेय के नेतृत्व में हजारों साथियों ने भाग लिया। कामरेड रामटहल पूर्वे सीपीआई मधुबनी के मजबूत स्तम्भ थे। वे पार्टी जिला कार्यकारिणी के सदस्य, कलुआही अंचल के मंत्री, बिहार राज्य किसान सभा के राज्य परिषद सदस्य थे। वे गरीबों के मसीहा थे, जीवनपर्यंत सीपीआई को मजबूत करने में दिन रात एक करते हुए, पार्टी अखबार एवं पत्रिका बेचकर पार्टी कार्यकर्ता एवं समर्थक के बीच वामपंथी प्रगतिशील विचारों को प्रचार–प्रसार में लगे रहते थे। वे छात्र जीवन में ही कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए थे। अंतिम समय तक पार्टी के कार्य करते रहे। भाकपा राज्य सचिव ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि शहीद कामरेड रामटहल पूर्वे के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने राज्य सरकार से हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी की सजा सुनिश्चित कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कामरेड रामहटल पूर्वे की हत्या से लोगों में दहशत है, इसलिए पुलिस प्रशासन हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे नहीं तो भाकपा आंदोलन के लिए बाध्य होगी।

भाजपा हटाओ, देश बचाओ

मोदी सरकार से प्रेस की आजादी को खतरा

महेश राठी

फासीवाद की विशेषताओं में से एक मीड़िया को नियंत्रित करते हुए उसे सरकार का भौंपू बना देना होती है। क्योंकि फासीवादी ताकतें जानती हैं कि एक स्वतंत्र मीड़िया ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती और स्वाभाविक और मजबूत विपक्ष होता है। इसीलिए फासीवादी देशों का मीडिया पूरी तरह सरकार के अधीन होता है। या तो उन्हें खरीद लिया गया होता है, या फिर उन पर इस तरह का दबाव बनाया जाता है कि वे सत्ता पक्ष के विरुद्ध कोई खबर ना दिखाएं। मीडिया सरकार से सवाल करने की बजाय विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा करता है। वह आम जनता को उनके बुनियादी मुद्दों से भटकाकर उन्हें गैर–जरूरी उकसावे वाली भावुकता की खबरों में फंसाये रखता है। रात को प्राइम टाइम पर टीवी खोलिये न्यूज चैनल लगा लीजिए, सोफे पर खाना लेकर बैठ जाइए और देखिये किस तरह न्यूज एंकर हिन्दू–मुसलमान और सेना का नाम लेकर आपको मूर्ख बनाते हैं। मोदी सरकार के तहत हम फासीवाद की इन सभी विशेषताओं के साक्षी हैं।

फासीवाद की जरूरत नियंत्रित मीड़िया

मीड़िया को नियंत्रित करने के लिए सांप्रदायिक और कारपोरेट के गठजोड़ का प्रतिनिधित्व करने वाली आरएसएस–भाजपा के नेतृत्व वाली फासीवादी ताकतों ने सभी प्रकार की उपलब्ध रणनीतियों पर काम किया। अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए देश और दुनिया का कारपोरेट चाहता था मोदी सत्ता में आये। जिसके लिए उसने 2014 से पहले ही तैयारियां शुरू कर ली थी। 2014 के आम चुनावों के ठीक पहले से ही मोदी के करीबी माने जाने वाले देश के सबसे बड़े धनवानों अंबानी और अडानी ने मीड़िया को खरीदना और मोदी के पक्ष में उसकी संपादकीय नीतियों को बदलने का काम शुरू कर दिया था। देश के लगभग सभी प्रमुख सामाचार माध्यमों पर उनकी पकड़ बन चुकी थी और वे मोदी के चुनाव प्रचारक की तरह काम करने लगे थे। उसके बाद चुनावों में जीत के बाद मोदी सरकार ने सरकारी मशीनरी के माध्यम से मीड़िया पर पूरी तरह से लगाम कसने की मुहिम शुरू कर दी थी और जिसमें वह पूरी तरह से कामयाब रहे। वह मीड़िया को विज्ञापन देना हो अथवा विभिन्न सरकारी एजेंसियों यथा सीबीआई, ईडी और आयकर का इस्तेमाल करना हो चाहे फिर मोदी विरोध को देश विरोध कहकर पत्रकारों पर राजद्रोह के केस दर्ज करना हो, फासीवादी ट्रोल आर्मी का इस्तेमाल हो अथवा फासीवादी गुण्ड़ों द्वारा सीधा हमला करवाना हो। मोदी सरकार ने मीड़िया को नियंत्रित करने के लिए मीड़िया घरानों और पत्रकारों की खरीद से लेकर उत्पीडन करने तक हर हथकण्ड़ा अपनाया है।

फ्रीडम हाउस के वार्षिक मीडिया स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार सन् 2014 के चुनाव अभियान के दौरान मालिकों द्वारा मीडिया में प्रकाशित होने वाली सामग्री में हस्तक्षेप की घटनाओं में वृद्धि हुई व (राजनैतिक कारणों से) कई प्रमुख संपादकों को नौकरी से हटाया गया। चुनाव अभियान के दौरान और भाजपा की विजय के बाद, कई पत्रकारों ने यह कहा कि प्रबंधन द्वारा उन पर यह दबाव डाला जा रहा है कि मोदी की आलोचना ना की जाए। एक टीवी कार्यक्रम के एंकर को इसलिए नौकरी से हटा दिया गया क्योंकि उसने यह कहा कि लोगों को मोदी को वोट देने के पहले सोचना चाहिए।

इसके अलावा दैनिक समाचार पत्र 'द हिन्दू' में जानेमाने डाक्यूमेंन्ट्री निर्माता आनंद पटवर्धन ने भाजपा पर यह आरोप लगाया कि वह राज्यतंत्र की ताकत और शारीरिक हिंसा के जरिए अपना सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रही है। अपने लेख में उन्होंने कहा कि हम बाजार की सेंसरशिप का सामना कर रहे हैं और निष्पक्ष टीवी कवरेज पाना मुश्किल होता जा रहा है। वे कारपोरेट घरानों द्वारा मीडिया कंपनियों को खरीदे जाने के संदर्भ में बात कर रहे थे। ये कारपोरेट घराने, राष्ट्रीय मीडिया को अपना कैदी बनाना चाहते हैं। मीडिया हमें नहीं बता रहा है कि हमारी दुनिया में क्या हो रहा है। मीडिया पूरी तरह चुप है। जहाँ एक तरफ सरकार का कहना रहा है कि ये नियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पारदर्शिता की कमी से निपटने और एक मजबूत शिकायत निवारण व्यवस्था बनाने की मंशा से लाए गए हैं, वहीं सोशल मीडिया और न्यूज मीडिया कंपनियाँ इन नियमों को अभिव्यक्ति की आजादी को रोकने की एक कोशिश के रूप में देखती रहीं हैं।

प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में गिरती रैंक

भारत की इस बदतर होती स्थिति के बारे में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण मीडिया और मीडिया स्वामित्व का केंद्रीकरण सभी दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और हिंदू राष्ट्रवाद के अवतार नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 से शासित 'दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र' में प्रेस की स्वतंत्रता संकट में है।

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) ने 3 मई को अपने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का 21वां संस्करण जारी किया और यह भारत में प्रेस कर दुर्दशा को रेखांकित करने के उपयुक्त दस्तावेज की तरह है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में 180 देशों की सूची में भारत 161वें पायदान पर रहा। बीते वर्ष की तुलना में भारत की रैंक 11 स्थान नीचे गिरी है। वर्ष 2022 में भारत 150वें पायदान पर रहा था। इस प्रकार भारत उन 31 देशों में शामिल है, जहां आरएसएफ का मानना है कि पत्रकारों के लिए स्थिति 'बहुत गंभीर' है। मोदी के सत्ता पर काबिज होने के बाद से भारत में प्रेस की आजादी का लगातार हनन होता जा रहा है। यदि पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को ही लें तो 2016 में भारत 133वें स्थान पर था तो 2017 में फिसलकर 136वें स्थान पर चला गया था और वहीं 2019 में भारत जहां 140वें स्थान पर था तो वहीं 2020 में यह गिरकर 142वें स्थान पर चला गया था और 2022 में यह 150वें स्थान पर रहा तो 2023 में 11 अंक गिरकर 161 स्थान पर आ चुका है। इस रैंकिंग में सबसे भयावह पहलू यह है कि इस रैंकिंग में तालिबान के कब्जे वाला अफगानिस्तान और पड़ोसी पाकिस्तान भी बेहतर स्थिति में हैं।

मीड़िया और राजद्रोह

पिछले कुछ सालों से लगातार मीडिया और पत्रकारों के ऊपर राजद्रोह के मुकदमे दर्ज किये गए हैं। किसानों की ट्रैक्टर रैली के मामले में नोएडा पुलिस ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर सहित छह पत्रकारों पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। केस एक शिकायत पर दर्ज किया गया था जिसमें आरोप लगाया था कि इन लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट्स और डिजिटल प्रसारण राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा के लिए जिम्मेदार थे।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रसिद्ध पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के शिमला में दर्ज देशद्रोह के मामले को खारिज कर दिया था। दुआ के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के एक स्थानीय भाजपा नेता ने उनके यूट्यूब शो को लेकर मामला दर्ज कराया था। दुआ पर देशद्रोह सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाया गया था और भाजपा नेता ने दावा किया था कि दुआ ने 30 मार्च, 2020 को अपने 15 मिनट के यूट्यूब शो में अजीबोगरीब आरोप लगाए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोट पाने के लिए मौतों और आतंकी हमलों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। इस मामले में अदालत ने कहा कि प्रत्येक पत्रकार केदारनाथ सिंह के फैसले के तहत सुरक्षा का हकदार है जिसमे धारा 124ए के तहत राजद्रोह के अपराध के दायरे को परिभाषित किया गया है।

वहीं अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और तीन अन्य लोगों पर राजद्रोह सहित विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया था। कप्पन एक कथित हाथरस सामूहिक बलात्कार मामले की रिपोर्ट करने के लिए हाथरस जा रहे थे। ठीक उसी महीने मणिपुर के पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया। वांगखेम को 2018 में भी राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत आरएसएस, मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। अप्रैल 2019 में उनके खिलाफ आरोपों को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया। 05 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट लिखने के चलते केरल के कोल्लम जिले में सीपीआई (एम) कार्यकर्ता राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था।

देश में पत्रकारों को धमकाने और उन्हें उनका काम करने से रोकने की घटनायें बढ़ रही हैं। पत्रकार पहले से कहीं अधिक खतरे में हैं। केंद्र और राज्यों की सरकारें सुरक्षा, आपराधिक मानहानि व घृणा फैलाने वाले भाषणों से संबंधित कानूनों का दुरूपयोग कर रही हैं और यहां तक कि अदालतों की अवमानना और देशद्रोह के आरोप लगाकर, उन सभी व्यक्तियों को हतोत्साहित और डराने का प्रयास कर रही हैं जो सत्ताधारी पार्टी का विरोध करते हैं अथवा उन अपराधियों के कुकर्मो का खुलासा करते हैं जो राजनीतिज्ञों के करीबी हैं या ऐसी कोई भी बात लिखते हैं जिससे सरकार को परेशानी होती है। केंद्र व राज्य स्तर पर होने वाले चुनावों के दौरान 'पेड न्यूज'–अर्थात उम्मीदवारों द्वारा समाचार के रूप में विज्ञापन के प्रकाशन–पर रोक लगाने के प्रयास भी कुछ हद तक इसी अभियान का हिस्सा हैं। इसके साथ ही केंद्रीय व राज्य सरकारें कुछ कानूनों का सहारा लेकर पिछले दरवाजे से प्रेस पर सेंसरशिप लगा रही हैं।

नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, भारत में साल 2015 में 30, 2016 में 35, 2017 में 51, 2018 में 70 और 2019 में ऐसे 93 राजद्रोह के मामले दर्ज हुए। 2019 में देश में जो 93 राजद्रोह के मामले दर्ज हुए और 96 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन 96 लोगों में से 76 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई और 29 को बरी कर दिया गया। इन सभी आरोपियों में से केवल दो को अदालत ने दोषी ठहराया। 2018 में जिन 56 लोगों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया उनमे से 46 के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई और उनमें से भी केवल 2 लोगों को ही अदालत ने दोषी माना था। इसी तरह 2017 में जिन 228 लोगों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया उनमें से 160 के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई और उनमे से भी मात्र 4 लोगों को ही अदालत ने दोषी पाया। 2016 में 48 लोगों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उनमें से 26

शेष पेज 15 पर...

गांधीजी की शहादत, गोडसे और आरएसएस का इतिहास

राम पुनियानी

हाल में (अप्रैल 2023) में एनसीईआरटी ने स्कूली पाठ्यपुस्तकों में से बहुत सी सामग्री हटाने का फैसला किया। हटाई गई सामग्री में मुगलकालीन इतिहास, गुजरात दंगे, वर्ण व्यवस्था के उदय के साथ–साथ गांधीजी की हत्या से संबंधित कुछ विवरण भी शामिल है। ''हिन्दू–मुस्लिम एकता के लिए उनके (गांधीजी) निरंतर प्रयासों से हिन्दू अतिवादी इस हद तक भड़क गए कि उन्होंने गांधीजी की हत्या के कई प्रयास किए...गांधीजी की मृत्यु का देश की साम्प्रदायिक स्थिति पर लगभग जादुई प्रभाव हुआ..भारत सरकार ने साम्प्रदायिक घृणा फैलाने वाले संगठनों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की...राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया. .."। जहां इस विवरण को हटाए जाने की कड़ी आलोचना हो रही है वहीं आरएसएस के नेता राम माधव ने द इंडियन एक्सप्रेस के 22 अप्रैल 2023 के अंक में प्रकाशित अपने लेख में इस आलोचना की आलोचना की है। उन्होंने इस निर्णय का बचाव करते हुए उस हिस्से को हटाने को उचित बताया है जिसमें हत्यारे गोडसे को हिन्दू अतिवादी, अग्राणी नामक हिंदू अतिवादी समाचारपत्र का संपादक और महाराष्ट्र का ब्राम्हण बताया गया है।

वे अपने लेख की शुरूआत एक मुस्लिम अब्दुल रशीद द्वारा स्वामी श्रद्धानंद की हत्या के विवरण से करते हैं। गांधीजी ने इस हत्या की आलोचना की लेकिन रशीद को भाई कहकर संबोधित किया और कहा कि इस हत्या के लिए उसे दोषी नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि दोषी उन्हें माना जाना चाहिए जिन्होंने नफरत का माहौल बनाया। लगता है माधव यह कहना चाहते हैं कि रशीद और गोडसे का रवैया एक–दूसरे के विपरीत था जबकि सच्चाई इससे उलट है।

बेशक अपनी हत्या के बाद गांधीजी, गोडसे के बारे में अपनी राय देने के लिए मौजूद नहीं थे लेकिन इस कायराना कृत्य के बारे में उनका रवैया तभी साफ हो गया था जब सन् 1944 में गोडसे ने पुणे के पास पंचगनी में उन पर एक खंजर से हमला करने का प्रयास किया था। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था, ''उस शाम एक प्रार्थना सभा के दौरान गोडसे, जो नेहरू शर्ट, पजामा और जैकिट पहने हुए था, गांधीजी की ओर लपका। उसके हाथ में एक खंजर था और वह गांधी–विरोधी नारे लगा रहा था। लेकिन गोडसे को काबू में कर लिया गया..." और गांधीजी की जान बच गई। इस पर गांधीजी ने गोडसे से कहा कि वह ''आठ दिनों तक उनके साथ रहे ताकि वे दोनों एक दूसरे को समझ सकें"। गोडसे ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और उदार ह्दय गांधीजी ने उसे वहां से जाने दिया। इस तरह अब्दुल रशीद और गोडसे, दोनों के मामले में गांधीजी की प्रतिक्रिया एक सी थी।

जहां तक गांधीजी द्वारा घृणा को स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की वजह बताने का सवाल है, यही मत संघ पर प्रतिबंध लगाने वाले गांधीजी के शिष्य सरदार पटेल का था। माधव का यह कहना गलत है कि नेहरू की जिद के कारण संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। वास्तविकता गृह मंत्रालय, जो कि सरदार पटेल के पास था, द्वारा जारी विज्ञप्ति से जाहिर होती है। चार फरवरी 1948 को जारी विज्ञप्ति में केन्द्र सरकार ने कहा कि ''देश की स्वतंत्रता को खतरे में डालने और उसको बदनाम करने में रत घृणा और हिंसा फैलाने वाली शक्तियां, जो हमारे देश के अच्छे नाम को बदनाम कर रही हैं, को समूल उखाड़ने के लिए आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है...यह पाया गया है कि देश के कई भागों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोग आगजनी, लूट डकैती और हत्या जैसे हिंसक कृत्यों में शामिल रहे हैं और उन्होंने अवैध हथियार और असलहा जमा किया है। उन्हें ऐसे पर्चे वितरित करते हुए पाया गया है जिनमें लोगों को आतंकवादी हमलों हथियार एकत्रित करने, सरकार के खिलाफ असंतोष फैलाने और पुलिस व सेना को विद्रोह के लिए उकसाने का प्रयास किया गया है। एम. एस. गोलवलकर को संबोधित एक पत्र में पटेल ने लिखा, ''उनके (आरएसएस के सदस्यों के) भाषण साम्प्रदायिक जहर से भरे होते थे...इस जहर का अंतिम नतीजा यह हुआ कि देश को गांधीजी के अमूल्य जीवन का बलिदान देना पड़ा। जनता और सरकार में आरएसएस के प्रति जरा सी भी सहानुभूति बाकी न रही। यह विरोध तब और प्रबल हो गया जब आरएसएस वालों ने गांधीजी की मौत पर हर्ष व्यक्त किया और मिठाईयां बांटीं।'' संघी विचारक माधव का कहना है कि आरएसएस पर प्रतिबंध का जिक्र अर्धसत्य है क्योंकि अदालतों ने प्रतिबंध को अवैधानिक घोषित कर हटा दिया था। किंतु जो अनुच्छेद हटाया गया है उसमें ठीक यही लिखा था कि प्रतिबंध केवल कुछ समय के लिए लगाया गया था। वैसे गांधी से लेकर पटेल और नेहरू तक सभी को इस बात का अहसास था कि एक व्यक्ति के रूप में गोडसे से अधिक घृणा का माहौल गांधीजी और स्वामी श्रद्धानंद की हत्या सहित हिंसा की सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार था। यद्यपि आरएसएस पर प्रतिबंध वैधानिक दृष्टि से वैध नहीं पाया गया, किंतु प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था क्योंकि आरएसएस द्वारा घृणा फैलाई जा रही थी जिसके नतीजे में हिंसा और गांधीजी की हत्या समेत हत्याएं हो रहीं थीं। आरएसएस गांधीजी की तारीफ करते नहीं थकता लेकिन वह आज भी वही कर रहा है जो शुरू से करता आया है–मुसलमानों के प्रति घृणा फैलाना और साथ ही प्राचीन पदानुक्रमित समाज का महिमामंडन करना। गोडसे के मन में जो घृणा भरी थी वह आरएसएस की देन थी। गोडसे लिखता है, ''हिन्दुओं के उत्थान का कार्य करते हुए मुझे अहसास हुआ कि हिन्दुओं के न्यायपूर्ण हितों की रक्षा के लिए देश की राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेना आवश्यक है। इसलिए मैं संघ (आरएसएस) छोड़कर हिन्दू महासभा में शामिल हो गया" (गोडसे, 'वाय आई एसेसीनेटिड महात्मा गांधी' 1993, पृष्ठ 102)। वह महात्मा गांधी को मुसलमानों के तुष्टिकरण का और उसके नतीजे में पाकिस्तान के निर्माण का दोषी मानता था। वह उस समय के एकमात्र हिन्दुत्ववादी राजनैतिक दल, हिन्दू महासभा में शामिल हुआ और उसकी पुणे शाखा का महासचिव बना। बाद में उसने अग्राणी या हिन्दू राष्ट्र नामक एक अखबार का प्रकाशन किया, जिसका वह संस्थापक संपादक था।

अब्दुल रशीद और गोडसे के दिलों में भरी घृणा को आज के संदर्भ में ऐसे समझा जा सकता है कि धार्मिक जुलूसों में लाठी और तलवार घुमाते और पिस्तौल लेकर चलने वाले युवा बेशक दोषी हैं लेकिन उनसे अधिक दोषी है बांटने वाली, घृणा भरी विचारधारा, नफरत भरे भाषण और सोशल मीडिया, जो लगातार धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति द्वेष फैलाती है। यदि हम अपने पड़ोस की ओर देखें तो इस बात की पुष्टि होती है कि धर्म आधारित राष्ट्रवाद का मुख्य आधार होता है घृणा उत्पन्न करना और उसे फैलाना। एक तरह से हम पाकिस्तान और श्रीलंका के रास्ते पर चल रहे हैं। पाकिस्तान में इस्लामिक राष्ट्रवाद के चलते हिन्दुओं और ईसाईयों के खिलाफ लोगों के दिलों में भरी नफरत के नतीजे में उनकी प्रताड़ना हो रही है। श्रीलंका में बौद्ध सिंघली राष्ट्रवाद से उत्पन्न घृणा का नतीजा हिन्दू (तमिल), मुसलमान और ईसाई भुगत रहे हैं। अब पाठ्यपुस्तकों में किए गए इन विलोपनों के साथ हिन्दू राष्ट्रवादी और उनके समर्थक घृणा की उस आग को और भड़का रहे हैं जो कई हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेदार है और जिससे अल्पसंख्यक अलग–थलग पड़ रहे हैं। ये विलोपन, विशेषकर गांधीजी की हत्या एवं उसमें आरएसएस की भूमिका, वर्तमान समय के घृणा फैलाने के एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक और प्रयास है। (अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया)

मई दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया

सारण: मकेर अंचल प्रखंड मुख्यालय में मई दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया प्रारंभ में मुख्तार राय ने लाल झंडा फहराया और शहीद वेदी पर माल्यार्पण कर शहीदों के रास्ते चलने का संकल्प लिया। आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व जिला सचिव ने मई दिवस के इतिहास पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि आज हिंदुस्तान में काम कर रही भारतीय जनता पार्टी सरकार 150 वर्षो के संघर्ष से अर्जित तमाम मजदूर कानून को निरंतर अपने यार पूंजीपतियों की संपत्ति को बढ़ाने के काम में व्यस्त हैं। हड़ताल सामूहिक बारगेनिंग जैसे अधिकार से मजदूरों को वंचित किया जा रहा है। तो आइए इस मौके पर सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों को प्राप्त करने हेतु आंदोलन का संकल्प लें।

समारोह की अध्यक्षता मोहन राय और शिवपूजन साह, सुरेंद्र राम, महात्मा जी, जयपाल राय, लाल बाबू यादव, राजेश्वर सिंह ने संबोधित किया।

इंदौर

1 मई अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस एटक कार्यालय शहीद भवन इंदौर पर मनाया गया। सर्वप्रथम ध्वजारोहण किया जाकर अंतरराष्ट्रीय गान गाया गया, बाद में कार्यकर्ता सभा की गई, जिसकी अध्यक्षता एटक जिला अध्यक्ष व पूर्व पार्षद सोहनलाल शिन्दे ने की। इस अवसर पर ओमप्रकाश खटके, विजय दलाल, विवेक मेहता, विनीत तिवारी, सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री जया मेहता एवं सारिका श्रीवास्तव अपने विचार रखें, तथा राष्ट्रीय मानावाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो की म.प्र. अध्यक्षा सुश्री प्रीति कानूनगों ने आजीवन श्रमिक वर्ग की सेवा करने के लिए एटक अध्यक्ष सोहनलाल शिंदे, महासचिव रूद्रपाल यादव एडवोकेट, ऑल इंडिण्या बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अरविन्द पोरवाल एवं ऑल इंडिण्या लॉयर्स यूनियन की इंदौर ईकाई के उपाध्यक्ष एडवोकेट ओमप्रकाश खटके को "श्रमिक सेवा सम्मान प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। सभा का संचालन रूद्रपाल यादव ने किया।

इस अवसर पर सत्यनारायण वर्मा, सखाराम जाडकर, विशाल प्रजापति, अशोक प्रजापति खलोफा, रमेश झाला, दिलीप कौल ने सभी को मई दिवस की शुभकामनाऐं दी एवं शाम 6 बजे पाटनीपुरा चौराहा से मालवा मिल चौराहे तक पैदल रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व रूद्रपाल यादव, कैलाश लिम्बोदिया, प्रमोद नामदेव इसके पश्चात मालवा मिल चौराहा पर संयुक्त आम सभा की गई। जिसकी अध्यक्षता सोहनलाल शिंदे ने की। आमसभा को एटक से ओमप्रकाश खटक, सीटू से सी एल सर्रावत, भागीरथ कछवाह, कैलाश लिम्बोदिया एआईयूटीयूसी के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश शर्मा, प्रमोद नामदेव बैंक एम्पलॉईज एसोसिएशन से रामदेव साइडीवाल, मेडीकल रीप्रेजेन्टेटिव एसोसिएशन की और से मनीष ठक्कर, बीएसएनएल एम्पलॉईज एसोसिएशन की और से प्रकाश शर्मा, इंश्योरेंस एम्पलॉईज यूनियन की और से अजीत केतकर, इंदौर डिवीजन इंश्योरेंस एम्पलॉईज एसोसिएशन की और से सुबीर भारतीय किसान संघर्ष समिति की और से रामस्वरूप मंत्री, किसान सभा से अरूण चौहान ने संबोधित किया भारतीय महिला फेडरेशन की और से सारिका श्रीवास्तव ने संबोधित किया एवं विलास, रमेश पाटिल, संजय मौर्या, समाजवादी नेता रामबाबू अग्रवाल, अरविन्द पोरवाल, विवेक मेहता, विनित तिवारी, जया मेहता, अजय कुमार बागी, कैलाश गोठानिया, ने भी शुभकामना संदेश दिये।

इस मौके पर नुक्कड नाटक 'मशीन' का मंचन भी किया गया। आमसभा का संचालन रूद्रपाल यादव ने किया पीथमपुर जिला धार के औद्योगिक क्षेत्र में भी हर्षोल्लास के साथ मई दिवस मनाया गया। इस मौके पर कपारो इंजिनियरिंग वर्कर्स यूनियन, एल.एण्ड.टी. कंट्रक्शन मजदूर संगठन, इंजीनियरिंग मजदूर संगठन के श्रमिकों ने अपने कार्यस्थल पर झंडा वंदन कर रैली निकालकर कार्यकर्ताओं की सभा कर मिठाई वितरण कर मई दिवस मनाया। इस मौके पर धार जिला एटक समिति के अध्यक्ष रूद्रपाल यादव, महासचिव यशवत पैठणकर ने ध्वजारोहण कर आमसभा को संबोधित किया। इस मौके पर श्रमिक नेता राजेश सुर्यवंशी, तेजलाल पटेल, सत्यनारायण यादव, संतोष गौरी, उमेश नागर, श्यामसुंदर सोनी, संतोष पटेल भी मौजूद रहे।

भारतीय महिला फेडरेशन का कुश्ती पहलवानों को समर्थन

भाजपा सांसद के खिलाफ देशभर में सड़कों पर महिलाएं

भारतीय महिला फेडरेशन ने आंदोलनकारी कुश्ती पहलवानों का समर्थन करते हुए देशभर में महिलाओं को सड़कों पर उतरने और आरोपी को सजा दिलावाने का आह्वान किया। एनएफआइडब्ल्यू ने बृज भूषण के तत्काल निलंबन की भी मांग की है। बृज भूषण शरण सिंह सांसद के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन शोषण और आपराधिक धमकी के लिए पोक्सो और पोश अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वूमेन ने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला को उनके कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है। जिसमें आरोपी सांसद को लोकसभा से तत्काल निलंबित करने की मांग की गयी।

ज्ञापन पर क्रमशः अरुणा रॉय और एनी राजा, अध्यक्ष और महासचिव द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष से महिलाओं के सम्मान और संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों को बनाए रखने और संसद और आपराधिक न्याय प्रणाली में विश्वास को मजबूत करने के लिए तुरंत कार्य करने के लिए कहा गया है।

इसके अलावा एनएफआईडब्ल्यू ने देशभर में महिला कुश्ती पहलवानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने और हस्ताक्षर अभियान चलाने का भी आह्वान किया। जिसके जवाब में देशभर में एनएफआईडब्ल्यू की कार्यकर्ताओं ने पहलवानों के समर्थन में अभियान का आगाज कर दिया है।

केरल में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। जिसकी उद्घाटन राज्यसभा सांसद पी संदोषकुमार ने किया और इस अभियान को पूरे राज्य में ले जाने का आह्वान किया।

चण्डीगढ़ में भी महिलाओं ने एनएफआईडब्ल्यू के नेतृत्व में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और धरने पर बैठी लंबे समय से न्याय मांग रही महिला पहलवानों के लिए न्याय की मांग की।

गिरधारी पुरा (राजस्थान)

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन (एनएफआईडब्ल्यू) राजस्थान ने दौ सौ फीट बाई पास गिरधारी पुरा मे रैली निकाल कर महिला खिलाडियों का पुरजोर समर्थन किया। युवतियों और महिलाओं ने नारों के माध्यम से भाजपाई यौन उत्पीड़नकर्ता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न नही सहेंगे, भाजपा डूब मरो शर्म करो, बृजभूषण शरण सिंह को गरिफ्तार करो, हम महिला रेसलर के साथ हैं, दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, बृजभूषण नही डरते तेरी घुड़की से खींच लेंगे कुर्सी से, फाईट फार जस्टिस, वी वांट जस्टिस आदि नारे लगाते हुए गहरा रोष जाहिर किया गया।

सभा को निशा सिद्धू महासचिव, मीनाक्षी और बोबी ने संबोधित किया।

हाकी खिलाड़ी आरती मीना सहित 21 युवा महिला खिलाडियों ने एनएफआईडब्ल्यू की सदस्यता ग्रहण की और आज के विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर महिला खिलाडियों का भरपूर समर्थन किया।

बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया।

आखिर में मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन का समापन हुआ।

पटना (बिहार)

जंतर– मंतर पर न्याय के लिए लड़ रही खिलाड़ियों के समर्थन में बिहार महिला समाज द्वारा 5 मई को प्रतिरोध मार्च निकाला गया। इस भयानक धूप में दर्जनों महिलाओं ने पहलवान खिलाड़ियों के प्रति अपनी एकता प्रदर्शित की। महिलाओं ने बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी और खिलाड़ियों को न्याय देने की मांग करते हुए कहा कि मोदी सरकार बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है। खिलाड़ियों के प्रति सरकार का रवैया शर्मनाक है।

बिहार महिला समाज की अध्यक्ष सुशीला सहाय, महासचिव राजश्री किरण, कार्यकारी अध्यक्ष निवेदिता झा, कृष्ण देवी, शाइस्ता अंजुम सहित कई महिलाओं ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। और अपनी एकता महिला खिलाडियों के प्रति दिखाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बलात्कारियों को बचाने में सरकार लगी है उससे जाहिर होता है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे झूठे हैं। जिन खिलाड़ियों पर देश नाज करता है आज उन्हें न्याय के लिए सड़क पर आना पड़ा। हम सरकार को आगाह करते हैं कि वे इन खिलाड़ियों की मांग को माने और अपराधियों को गिरफ्तार करें नहीं तो देश भर में ये आंदोलन तेज होगा।

केरल

गिरधारीपुरा, राजस्थान

मोदी सरकार एक जोंक की तरह है, जो आम जनता का खून चूसती है

हैदराबाद: भाकपा के राष्ट्रीय सचिव डॉ. के नारायणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार एक जोंक की तरह है जो आम लोगों का खून चूसती है और लोग करों के बोझ से दबे हुए हैं जिसे वे सहन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में भारत धीरे–धीरे कमजोर हो रहा है और गरीबी, बेरोजगारी और असमानता में काफी वृद्धि हुई है।

भाकपा ने हैदराबाद, पंजागुट्टा, नागार्जुन सर्कल और बंजारा हिल्स में 'भाजपा हटाओ–देश बचाओ' के नारे के साथ प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की जनविरोधी और निरंकुश नीतियों की निंदा करने के लिए 2 मई को एक मार्च निकाला। भाकपा के राष्ट्रीय सचिव डॉ.के.नारायण, भाकपा तेलंगाना राज्य सचिवमंडल सदस्य ई. टी. नरसिम्हा, भाकपा हैदराबाद जिला सचिव एस. छायादेवी के साथ भाकपा कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया और लोगों को भाजपा की जनविरोधी नीतियों के बारे में समझाते हुए व्यापारिक समुदाय को पत्रक वितरित किए और उनसे अगले चुनाव में भाजपा को हराने की अपील की।

इस अवसर पर डॉ. के. नारायण ने कहा कि मोदी सरकार के दौरान अडानी और अंबानी जैसे कुछ निवेशकों का मुनाफा काफी बढ़ गया है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और बैंक डूब रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के गलत फैसलों के कारण लाखों लोगों की आजीविका छिन रही है और देश की अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की कि ईंधन, आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और आम लोगों को ऐसी स्थिति में धकेला जा रहा है जहां वे नहीं रह सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार लोगों में नफरत भड़का रही है और संविधान, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को खत्म कर रही है। डॉ. के नारायणा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का हर वादा झूठा है, अगले चुनाव में भाजपा और मोदी के फर्जीवाड़े को हराना चाहिए और जनता को सबक लेना चाहिए। ई. टी. नरसिम्हा ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर एक राष्ट्र–एक जाति और धार्मिक घृणा के नारे के साथ शिक्षा, कला, संस्कृति और धर्म के मूल सिद्धांतों को नष्ट करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने राष्ट्रीय विकास और रोजगार सृजित करने में घोर विफलता के लिए केंद्र की भाजपा सरकार की आलोचना की। ई. टी. ने कहा कि लोगों को मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों पर ध्यान देना चाहिए और आने वाले चुनावों में उन्हें जवाब देना चाहिए। भाकपा हैदराबाद के जिला सहायक सचिव कामथम यादगिरी, बी. स्टालिन, राष्ट्र समिति के सदस्य बी. वेंकटेशम, जिला कार्यकारी सदस्य निर्लेकांति श्रीकांत, नेता अरुतला राज कुमार, शाकरी भाई, चेतन्य यादव, बाला कृष्ण, बी. राजू गौड़, कल्याण, मो. अहमद, अब्बास आदि शामिल हुए।

हम शमशान भूमि का निजीकरण रोकेंगे

भाकपा के राष्ट्रीय सचिव डॉ. के नारायणा ने कहा कि बागड़ी पेशेवरों का रोजगार छीनने वाले श्मशान घाटों के निजीकरण पर रोक लगेगी। उन्होंने हैदराबाद के पंजागुट्टा श्मशान घाट में बागड़ी पेशेवरों के साथ पदयात्रा का आयोजन किया और सार्वजनिक–निजी भागीदारी में बने श्मशान घाट का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हजारों साल से ये लोग कब्रिस्तान में काम कर रोजगार पा रहे हैं। के. नारायण ने चेतावनी दी कि अगर राज्य सरकार ने तुरंत जवाब नहीं दिया और श्मशान घाटों के निजीकरण को नहीं रोका तो भाकपा के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर संघर्ष छेड़े जाएंगे।

धर्मनिरपेक्ष और गैर–भाजपा दलों की सांप्रदायिक सद्भाव सभा

राम नरसिम्हा राव

ईद–मिलाप के अवसर पर रविवार को विजयवाड़ा के एमबीवीके में एक बैठक को संबोधित करते हुए गैर भाजपा और धर्मनिरपेक्ष नेताओं ने कहा कि, "धर्मनिरपेक्षता भारतीय दर्शन है। केवल सांप्रदायिक सद्भाव से ही देश का बचाव किया जा सकता है।''

यह बैठक आल इंडिया प्रोग्रेसिव फोरम, लौकिक राजयंगा परिरक्षण वेदिका, माकीनेनी बसबापुन्नैया विज्ञान केन्द्रम के तत्वावधान में आयोजित की गई। बैठक में 350 लोगों ने भाग लिया। बैठक का संचालन एम ए मैरिस, पिन्नामनेनी मुरली कृष्ण और बुद्दिगा जमींदार ने किया। वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद शफी ने मेहमानों और दर्शकों का स्वागत किया है, वहीं मोहम्मद नूरुद्दीन ने रमजान के महत्व के बारे में बताया। भाकपा (मा) के राज्य सचिव वी श्रीनिवास राव ने कहा कि हमारे देश का इतिहास सांप्रदायिक सद्भाव से भरा है। मोदी नीत भाजपा सरकार सांप्रदायिक तनाव भड़का रही है और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचा रही है। यह रामनवमी के अवसर पर, शोभायात्राओ के नाम पर अपनी जड़ें जमा रही है।

भाकपा राज्य सचिव मुप्पल्ला नागेश्वर राव ने कहा कि हम धर्मनिरपेक्षता और संविधान की रक्षा केवल भाजपा और उसके सहयोगी दलों को हराकर कर सकते हैं।

भाकपा राज्य सचिवमण्डल सदस्य और पूर्व राज्य विधायी सदस्य जल्ली विल्सन ने कहा कि यह दुखद स्थिति है कि राज्य में मुख्य पार्टियां सांप्रदायिक भाजपा का समर्थन कर रही हैं।

भाकपा (मा) के वरिष्ठ नेता पी मधु ने कहा कि हमारे संविधान की मुख्य विशेषताएं लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। इन विशेषताओं को खत्म करने के लिए भाजपा सरकार सभी प्रयास कर रही है। राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं।

कांग्रेस राज्य नेता नरहरसेट्टी नरसिम्हा राव ने कहा कि केंद्र सरकार का स्कूली पाठ्यक्रम से मुगलों के इतिहास को हटाना अन्याय है। राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता को रद्द करना केंद्र सरकार का प्रतिशोधात्मक कदम है। उन्होंने उनकी सदस्यता रद्द करने के एकतरफा कदम की कड़ी निंदा की।

एटक राज्य महासचिव जी ओबुलेसू ने कहा कि हमारे इतिहास में कोई अखंड भारत नहीं है, लेकिन भाजपा और आरएसएस अक्सर इस बारे में बात करते हैं। वे यह भी कहते थे कि वे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और हमारे संविधान को नहीं मानेंगे।

लॉरी ओनर्स एसोसिएशन के राज्य महासचिव वाईवी ईश्वर राव ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन और देश के विकास में सभी धर्मों ने अपना योगदान दिया है। इस पृष्ठभूमि में विशेष धर्म को लक्ष्य बनाना सही नहीं है।

इस अवसर पर वाईएसआर काँग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डा. महबूबबाद शेख, टीडीपी के प्रवक्ता सैयद रफी, भाकपा के राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य अक्किनेनी वनजा, भाकपा (मा) नेता बाबू राव, अवाज के राज्य संयोजक एमए चौथू, इंसाफ राज्य संयोजक अफसार, प्रजासाहिती के दिविकुमार, इफ्टू के पोलारी, एनएफआईडब्ल्यू की राज्य महासचिव पेनुमतसा दुर्गाभावनी, मोहिउद्दीन आदि मौजूद थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष डा. ए. रहमान ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया।

मंडी श्रमिक पर जानलेवा हमला करने वालों की हो गिरफ्तारी: एटक

जैतसर: विगत दिनों मंडी में पल्लेदारी का काम करने वाले श्रमिकों पर हुए जानलेवा हमले की नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाने के बावजूद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से श्रमिकों में नाराजगी है। पूरे प्रकरण की जानकारी लेने एवं घायल श्रमिकों से मिलने एटक राज्य महासचिव कुणाल रावत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जैतसर पहुंजा। एटक नेता कुणाल रावत ने श्रमिकों पर हुए इस कायराना हमले की निंदा की एवं पुलिस से मांग की कि आरोपियों की जल्दी गिरफ्तारी हो। उन्होंने कहा कि पूरा एटक संगठन घायल श्रमिकों के साथ खड़ा है। यूनियन प्रतिनिधियों ने व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजवीर सिंह से भी बात की। एटक प्रतिनिधिमंडल में एटक के सचिव केशव व्यास, राजस्थान खेत मजदूर यूनियन के संयोजक अवतार सिंह रामगढ़िया, राजस्थान किसान सभा के जिलाध यक्ष मुंशीराम कम्बोज, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के लखवीर मान, ऑल इंडिया स्टूडेंट फैडरेशन के नितिन बागड़ी, राजस्थान बिजली वर्कर्स फेडरेशन के सुरेश कुमार, हरदेव, पल्लेदार यूनियन के नेता ओमप्रकाश इंदोरा, फकीरा राम, महावीर, वकील इंदोरा, संदीप आदि शामिल हुए जिन्होंने बताया कि यदि जल्दी गिरफ्तारी नहीं हुई तो यूनियन आंदोलनात्मक कार्यवाही करेगी।

कामरेड बिंदेश्वर यादव नहीं रहे

छापरा: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी छपरा नगर परिषद के पूर्व सचिव जाने–माने श्रमिक नेता कामरेड बिंदेश्वर यादव का निधन पिछले दिनों 4 अप्रैल को उनके पैतृक आवास छपरा में हो गया। वह 75 वर्ष के थे उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे जिले भर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता किसान मजदूर उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें लाल सलाम करते हुए नेताओं ने अंतिम विदाई दिए। उनके निधन पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव सुरेंद्र सौरव, सुरेश वर्मा, रामबाबू सिंह, चूल्हन प्रसाद सिंह, रमेश ठाकुर, रतन प्रकाश सिंह, जवाहर मिश्र ने गहरा शोक व्यक्त किया और लाल झंडा झुका दिया गया। रामबाबू सिंह सदस्य राज्य परिषद ने प्रेस बयान के माध्यम से बताया कि कामरेड बिंदेश्वर महान क्रांतिकारी और पार्टी नेता थे उनके निधन से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सारण को अपूरणीय क्षति हुई है जिसे पूरा करना फिलहाल कठिन है।

डगमगाती अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत फासीवाद का उदय

डॉ. बी.के. कांगो

1930 में महामंदी के बाद कल्याणकारी अर्थव्यवस्था एक समाधान के रूप में सफल हुई।

फिर भी, जर्मनी और इटली ने स्पेन जैसे कुछ और देशों के साथ संकट से उभरने के लिए फासीवादी तरीके को अजमाया। उन्होंने ''अति राष्ट्रवाद'' की कोकटेल की और एकाधिकार (मोनोपोली) घरानों ने उनको समर्थन दिया था। वहां न केवल युद्ध के लिए उकसाया जा रहा था लेकिन उपभोग और मुनाफा वृद्धि को बढ़ावा दिया जा रहा था।

इस प्रक्रिया में छह करोड़ लोग मारे गए थे। लेकिन लाभ की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए युद्ध उपयोगी साबित हुआ। उनका नारा था ''लोग लाभ के लिए''। आज जब वैश्विक अर्थव्यवस्था 2008 के संकट से उभरने की कोशिश कर रही है तब अति राष्ट्रवाद युद्ध उद्योग प्रोत्साहन के रास्ते को इस संकट से उभरने के लिए उपयोग किया जा रहा है।

इस तरह से फासीवाद, एक दर्शन या घृणा और जनता की बजाय लाभ–आधारित विचारों का मिश्रण है। फासीवाद डर और घृणा के माध्यम से अति राष्ट्रवाद तैयार करता है। मुनाफाखोरों और उनके समर्थकों के उपरोक्त वर्णित प्रिय हथकंडे फिर से उभर रहे है।

हमें एक मानव नस्ल के रूप में इसका सम्मान करना है और शांतिपूर्ण विकास के लिए काम करना है। इस ''फासीवादी प्रक्रिया' के अंतर्गत जनतंत्र के सफर को खतरा है और हमें फासीवाद को हराने की जरूरत है। कुछ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के उदय के कारण वृद्धि दर में गिरावट ने विकसित देशों में वृद्धि की घटती दर को देखा है।

इस कारण नई आर्थिक नीतियों द्वारा चलाई गई प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार शुरू हुआ है और बात हो रही है कि पहले अमरीका या पहले भारत।

यह कुछ और नहीं केवल अति राष्ट्रवाद का आह्वान है और इसलिए बढ़ते तनाव की संभावनाएं और युद्ध जैसी परिस्थिति उभर रही है। अर्थव्यवस्था पर मंदी की मार के बाद पैदा हुई मुद्रास्फीतिजनित मंदी का सहारा लेकर राष्ट्रवादी अर्थव्यवस्थाओं को खोलने के लिए नई आर्थिक नीतियों को प्रोत्साहित किया गया।

लेकिन मुद्रा नीति को 40 साल चलाने के बाद और अधिकाधिक कल्याणकारी अर्थव्यवस्थाओं को हटाने के बाद मंदी का संकट, बेरोजगारी और आय असमानता वैसे ही बढ़ रही है जैसे कि विश्व बैंक का पूर्वानुमान था, वृद्धि दर भी नीचे गिर रही है।

बैंकों का डूबना–मुद्रा नीति के संकट का चिन्ह

अमरीका में सिलीकोन वैली समेत तीन बैंक डूब गए हैं और अब उनका अस्तित्व नहीं है। इसी तरह से एक बड़े स्विस बैंक, क्रेडिट सूसी को उनके प्रतियोगी स्विट्जरलैंड के यूबीएस बैंक ने ले लिया है। ऐसा इसलिए हुआ चूंकि इन बैंकों के शेयर दाम में भारी गिरावट हुई और बैंक के खाताधारकों ने बड़े पैमाने पर जमाराशि निकालीं।

शेयर दामों में गिरावट किसी धोखाधड़ी या कुप्रबंधन के कारण नहीं थी बल्कि इसका कारण अमरीका के फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा और यूरोप में यूरोपीय साधारण बैंकों द्वारा बढ़ाए गई ब्याज दर थी। इन केंद्रीय ऐजेंसियों को महंगाई का सामना करने के लिए ब्याज दर बढ़ानी पड़ी थी। अर्थव्यवस्था में उपलब्ध फंड में कटौती के समाधान के लिए यह एक विशिष्ट मौद्रिक समाधान इस उम्मीद से किया जाता है कि दोनों में कमी आएगी लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यह नवउदार अर्थव्यवस्था के वर्तमान रास्ते पर चलने की समस्या की ओर इशारा करता है।

बढ़ती बेरोजगारी, आय में असमानता और इस कारण लोगों में बढ़ती बेचैनी का समाधान करना चाहिए। जैसे कि इससे पहले की अर्थव्यवस्था के कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का मॉडल का पक्ष प्रसिद्ध अर्थशास्त्री केंस ने लिया था। उसका परिणाम भी मुद्रास्फीतिजनित मंदी में निकला। मिल्टन फ्रीडमैन का शिकागो मॉडल जो कि कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की जगह मौद्रिक नीति का पक्षधर है, इस मॉडल को 1980 के बाद से मुक्त रूप से चालू किया गया था लेकिन वह मॉडल भी अब संकट में है। सवाल है कि इससे निपटने का क्या तरीका है?

व्यापर के क्षेत्र से सरकार की वापसी यह कहकर कि व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं है, इस पर पुनर्विचार हो रहा है। मुनाफाखोर बहुराष्ट्रीय कंपनियां और एकाधिकारी घराने राज्य और इसकी दमनात्मक मशीनरी का इस्तेमाल जनता के बीच व्याप्त बेचैनी को दबाने के लिए करेंगे। अतः भारत समेत कई देशों में हमने देखा है कि ऐसी पार्टियों का फिर से उदय हो रहा है जो डर और घृणा को फैलाते हैं और बड़े एकाधिकार घरानों को समर्थन देते हैं।

वास्तव में सभी विकृतियों के साथ राष्ट्र राज्य की वापसी और इसकी अतिरिक्त दमनकारी शक्तियां फासीवादियों की पसंदीदा पद्धति है। मानवीय कल्याण के लिए और सभी देशों के बीच शांति और मैत्री के लिए प्रतिबद्ध सभी प्रगतिशील ताकतों के सामने एक चुनौती है। तिस पर भी, 1980 के बाद कल्याणकारी अर्थव्यवस्थाओं को नव उदारवादी नीतियों से बदल दिया गया जो कि सरकार को व्यवसाय से हटाने के बहाने केवल पूंजीपतियों की पक्षधर है।

अतः आज हमें संकट से सामना करने के लिए एक नई नीति को अपनाने की जरूरत है और यह केवल समाजवादी नीतियों के माध्यम से हो सकता है और महंगाई और बेरोजगारी की समस्या का समाधान राज्य के हस्तक्षेप से हो सकता है। इसे जनता के मुद्दों को प्रोत्साहित करने से हासिल किया जा सकता है और जन मुद्दों को मानवीय गतिविधियों के केंद्र में होना चाहिए और इसमें जनता का उपयोग आज की भांति लाभ कमाने के लिए नहीं हो। हमारी नीति लोगों के लिए लाभ वाली होनी चाहिए न कि लोगों की बदौलत लाभ।

किसी भी वैकल्पिक आर्थिक नीतियों पर विचार करने के लिए सरकार की भूमिका बहुत जरूरी है। वर्तमान नव उदारवादी व्यवस्था जनता के लिए सुविधाओं को खड़ा करने में सरकार की भूमिका को क्षीण करती है। वर्तमान परिस्थितियों में जब आर्थिक असमानता ऊंची होती जा रही है और सरकार समान अवसर के इंकार के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य से पीछे हट रही है, ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि सरकार की भूमिका पर जोर दे और शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के माध्यम से सभी के लिए समान अवसर के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने विजयवाड़ा में हुई अपनी 24वीं राष्ट्रीय कांग्रेस में ऐसा ही करने की अपील की है।

मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से देश की जनता तबाह

पटनाः बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन की राज्य परिषद की बैठक बुधवार को जनशक्ति भवन पटना में हुई। बैठक में भारतीय खेत मजदूर यूनियन का राष्ट्रीय सम्मेलन 2–5 नबम्बर 2023 को पटना में करने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर दो नबम्बर को विशाल रैली आयोजित की जायेगी। मनरेगा के सवालों को लेकर 30 मई को दिल्ली के जंतर–मंतर पर मनरेगा बचाओ प्रदर्शन किया जायेगा। बैठक की अध्यक्षता यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक सूर्यकांत पासवान ने की। बैठक को सीपीआई के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय, भारतीय खेत यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव गुलजार सिंह गोरिया, बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के महासचिव जानकी पासवान, उप महासचिव पुनीत मुखिया, कोषाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, सचिव अर्जुन राम आदि ने संबोधित किया।

बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय खेत मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव गुलजार सिंह गोरिया ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों से देश की जनता तबाह है। महंगाई आसमान छू रही है। मजदूरों पर लगातार हमले किये जा रहे हैं। मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। मोदी सरकार में मनरेगा के बजट में लगातार कटौती की जा रही है। कल्याणकारी योजनाओं की राशि घटाई जा रही है तो दूसरी तरफ पूंजीपतियों का कर्ज बट्टे खाते में डाला जा रहा है। मोदी सरकार देश को फासीवादी रास्ते पर ले जा रही है। देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता से भाजपा को हटाना है। इसके लिए जन संघर्ष को तेज करना होगा। देश में बेशुमार बेरोजगारी से आम लोग परेशान हो चुके है। केंद्र सरकार नौजवानों को रोजगार देने का वादा करने के वाबजूद रोजगार देने के बजाय अपने मजदूर विरोधी एवं पूंजीपति पक्षी

नीतियों को लागू करने में व्यस्त है। खेत मजदूर यूनियन के लगातार संघर्ष एवं आंदोलन के बदौलत मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना को केंद्रीय कानून का दर्जा मिला। केंद्र सरकार मनरेगा को समाप्त करने की साजिश कर रही है। आम बजट में मनरेगा में भारी कटौती की गई है। महंगाई की मार से मजदूर एवं किसान परेशान एवं तबाह है परिणामस्वरूप देश के विभिन्न हिस्सों में मजदूर–किसान आत्महत्या कर रहे है।

सीपीआई के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने कहा कि मोदी सरकार देश के तमाम संस्थाओं को पूंजीपतियों के हाथों बेच रही है। खेत मजदूर यूनियन संगठन को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के मजदूरों को संगठित कर धारदार आंदोलन करने की जरूरत है। घृणा पैदा कर देश और राज्य नही चलाया जा सकता। उन्होंने कहा बिहार के मध्यमवर्गीय जनता की आवाज बनकर, मेहनतकश किसान मजदूर के सवालों पर केंद्र सरकार को 2024 में सत्ता से उखाड़ फेंकना होगा। बिहार के बंद उद्योग को चालू करना, सभी बेघरों को घरों की व्यवस्था करना, आवासविहीन भूमिहीनों को 5 डिसमल जमीन देने, 600 रू न्यूनतम मजदूरी एवं साल में 200 दिन रोजगार देने की गारंटी करने के सवाल पर मजबूत संघर्ष करने की आवश्यकता है। दो नवम्बर को पटना में ऐतिहासिक रैली होगी। आठ और नौ जून को जिला मुख्यालय पर मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आयोजित जन सत्याग्रह और जेल भरो आन्दोलन में खेत मजदूरों को अधिक से अधिक संख्या में भाग लेना है।

भाजपा हटाओ, देश बचाओ

जारी है भाकपा का देशव्यापी जन जागरण अभियान

हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

भाजपा को अलग–थलग करने और हराने का पार्टी ने एकजुट संकल्प जताया है। यही आज देश, जनता और पार्टी का मुख्य काम है। 3 मई को नागर–लुम्बा भवन (भेल) हरिद्वार में संपन्न कैडर मीटिंग को सम्बोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अजीज पाशा ने उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि गुजरे 9 सालों में हमने देखा है कि भाजपा किस तरह अपने हाथ में आयी सरकार का इस्तेमाल कर, फासीवादी आरएसएस के हिन्दुत्ववादी साम्प्रदायिक एजण्डे को आक्रमक तरीके से आगे बढ़ा रही है। यही नहीं, निर्ममता से राष्ट्रीय परिसंपत्तियों को लूटा जा रहा है। भारत की आर्थिक संप्रभुता को कमजोर किया जा रहा है। सांप्रदायिक कारपोरेट गठजोड़ को मजबूत किया जा रहा है। बदतरीन किस्म के दरबारी पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। चुनावी बाण्डों के जरिए राजनीतिक भ्रष्टाचार को कानूनी बनाया जा रहा है और बाकायदा तानाशाही थोपकर जनता के जनतांत्रिक अधिकारों व नागरिक स्वतंत्रताओं को जिनकी गारण्टी हमारा संविधान करता है, पांवों तले रौंदा जा रहा है।

सत्ता में आने के बाद से भाजपा राज ने भारत के धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक संविधान के आधार स्तंभों को ही कमजोर करना शुरू कर दिया। मोदी सरकार की नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में डाल दिया है। अभूतपूर्व बेरोजगारी, बढ़ती गरीबी व भूख और बे–लगाम मंहगाई के प्रहार ने हमारे करोड़ों देशवासियों की रोजी–रोटी को तबाह कर दिया है। मोदी राज में आर्थिक असमानता की शर्मनाक और अमानवीय बढ़ोत्तरी हुई है। नफरत, आतंक और हिंसा के जरिए साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ाया जा रहा है। वामपंथी एकता

बिलासपुर

को आधार बनाकर तमाम जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष ताकतों की व्यापकतम गोलबंदी कर जन आंदोलन और सामाजिक आंदोलनों को भी अपने साथ शामिल करना होगा। देश के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा और उसकी विचारधारा को शिकस्त देना कम्युनिस्ट पार्टी की प्राथमिकता जिम्मेदारी है। उत्तराखण्ड में भी पार्टी को पदयात्रा कार्यक्रम को व्यापक रूप से गम्भीरता से अमल करना चाहिए।

बैठक को सम्बोधित करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय परिषद् के सदस्य समर भण्डारी ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने नौ साल में देश की जनतांत्रिक व्यवस्था और संविधान को बहुत भारी चोट पहुंचायी है। संसदीय जनतंत्र के पर कतरने, नागरिकों के जनतांत्रिक अधिकारों पर कैंची चलाने और संवैधानिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए जिम्मेदार तमाम संस्थाओं को भीतर से ध्वस्त करने की सुव्यवस्थित कोशिशों के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। संसद के अवमूल्यन तथा संसदीय प्रक्रियाओं के कमतर किए जाने ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में खासतौर पर भीषण रूप ले लिया है। अडाणी प्रकरण इसका गवाह है। जनतंत्र को हटाकर, उसकी जगह एक बहुसंख्यकवादी राज कायम करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा सरकार का केन्द्रीय सच यही है कि आरएसएस के हिन्दुत्व के एजेण्डे के हिसाब से भारतीय राज्य को नये सिरे से गढ़ने की मुसलसल मुहिम चला रही है।

कम्युनिस्ट कतारों को जमीनी तौर पर जनता के बीच फासीवादी राजनीति, संस्कृति, मूल्यों और विचारधारा को नंगा करते हुए उसे निष्प्रभावी बनाना होगा। भाकपा के आह्वान 'मोदी हटाओ देश बचाओ' का बुनयादी लक्ष्य यही है।

भाकपा प्रदेश सचिव जगदीश कुलियाल ने कहा कि ऐसे कठिन समय में फैसलों पर दृढ़ता से अमल करना पार्टी की प्राथमिकता होनी चाहिए। देहरादून, ऋषिकेश व कुछ अन्य स्थानों पर पार्टी द्वारा पद यात्राएं आयोजित कर पर्चे वितरित किए हैं। किन्तु अभी भी कई जिलों से कार्यक्रम की सूचना नहीं है। उत्तराखण्ड़ जैसे शांत क्षेत्र में भी भाजपा लगातार साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की मुहिम चलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। इसका प्रमाण हरिद्वार और देहरादून जनपद में आयोजित कथित धर्म संसद द्वारा फैलायी गयी घृणा और अल्पसंख्यकों का आर्थिक बहिष्कार का नारा है। पार्टी पूरे प्रदेश में दृढ़ता से पदयात्रा कार्यक्रम को आयोजित करेगी।

बैठक की अध्यक्षता पार्टी के वरिष्ठ नेता एम एस त्यागी व संचालन पार्टी के प्रदेश सहसचिव रवीन्द्र जग्गी ने किया। बैठक में प्रमुख रूप से अशोक शर्मा, एन. एस. नेगी, एम. एस. वर्मा, हरिनारायण, विजयपाल, रणजीत नेगी, मदन सिंह खालसा, सुभाष त्यागी, धर्मानन्द लखेड़ा, गुरमीत सिंह खालसा के. के. लाल, टी. के. वर्मा आदि उपस्थित थे।

पानीपत

पानीपत

मई दिवस के अवसर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं एटक ने संयुक्त रुप से पानीपत की देशराज कालोनी, 11 वार्ड, गणेश नगर, सैनी कार्लानी में दर्जन भर के करीब नुक्कड़ मीटिंग आयोजित की। नुक्कड़ मीटिंगों को सीपीआई के राज्य सचिव दरियाव सिंह कश्यप, जिला सचिव पवन सैनी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य राम रतन एडवोकेट, एटक नेता अशोक पंवार, किसान नेता मामचंद सैनी, सेवा सिंह मलिक आदि ने संबोधित किया। वक्ताओं ने मई दिवस के ऐतिहासिक महत्व पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि आज से 137 वर्ष पहले आज ही के दिन अमेरिका के शिकागो शहर में हजारो मजदूरों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग को लेकर हड़ताल की और प्रर्दशन किया। इन शांतिपूर्ण प्रर्दशनकारियों पर तत्कालीन अमेरिकी सरकार की पुलिस ने अंधाधुंध लाठीचार्ज किया और गोलियां बरसाते हुए कई मजदूरों को शहीद कर दिया। किसान मजदूर नेताओं ने कहा कि कालांतर में दुनिया भर में कानूनी तौर पर 8 घंटे कार्य दिवस होने के साथ–साथ मजदूरों की भलाई के लिए कानून बनाए गये लेकिन आज की भाजपा सरकार इन सभी हक अधिकारों पर हमले करके मजदूरों को गुलाम बनाना चाहती है, हमें एकजुट होकर सरकार की जनविरोधी, देशविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज करना होगा ।

वक्ताओं ने सीपीआई के जन जागरण अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि देश की आजादी और स्वतंत्रता के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अनेक संघर्षो में भाग लिया और देश के विकास के लिए संसद तथा संसद के बाहर अविस्मरणीय भूमिका अदा की। कम्युनिस्ट नेताओं ने देश की एकता–अखंडता की रक्षा के लिए संघर्षो के चलते अनेक बलिदान दिये। इन कार्यक्रमों में चन्द्रभान निम्बरी, भूपेन्द्र कश्यप, रुपेश सैनी, रामपाल सैनी सहित अनेक मजदूर शामिल हुए।

पानीपत में 2, 3, 4, मई को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भाजपा सरकार हराओ– देश बचाओ, संविधान बचाओ के नारे के साथ देशव्यापी राजनीतिक अभियान के तहत चले अभियान में रामनगर, बलजीत नगर, दलबीर नगर, निम्बरी, छाजपुर आदि गांवों में नुक्कड़ मीटिंगें की गई। इन दिनों के प्रचार जत्थों का नेतृत्व सीपीआई के राज्य कंट्रोल कमीशन के सदस्य मांमचंद सैनी, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य राम रतन एडवोकेट व जिला सचिव पवन कुमार सैनी ने किया। इन जत्थों में हरपाल सिंह कश्यप, चंद्रभान कनम्बरी, रामबीर, जमशेद राणा, भूल्लण, जय भगवान, भूपेन्द्र कश्यप, रुपेश सैनी, बिन्दर सिंह तोमर, शीश राम तंवर आदि शामिल रहे। इस दौरान दर्जनों नुक्कड़ मीटिंग की गई और पर्चे बांटें गये। नुक्कड़ मीटिंगों को मामचंद सैनी, पवन कुमार सैनी, राम रतन एडवोकेट सहित अन्य ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि देश की आजादी और स्वतंत्रता के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अनेक संघर्षो में भाग लिया और देश के विकास के लिए संसद तथा संसद के बाहर अविस्मरणीय भूमिका अदा की।

महान विचारक, दार्शनिक दुनिया के सर्वहारा वर्ग को गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास से मुक्त करने के लिए पूंजी व कम्युनिस्ट घोषणापत्र जैसे आदि ग्रंथो के रचनाकर, मेहनतकशों के मसीहा कार्ल मार्क्स की पावन जयंती पर 5 मई को भगत सिंह स्मारक पानीपत में उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया और पुष्प अर्पित किये गये। सीपीआई के राज्य सचिव दरियाव सिंह कश्यप, जिला सचिव पवन कुमार सैनी, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य राम रतन एडवोकेट सहित सतीश यादव, रणबीर सिंह देशवाल नम्बरदार, जोगेन्द्र सिंह, भूपेन्द्र कश्यप, मोहम्मद नईम, संजीत तिवारी, भानुप्रताप सैनी, रामदास, शीशराम तोमर आदि1 ने कार्ल मार्क्स के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया ।

इसके बाद सीपीआई कार्यकर्ताओं ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भाजपा सरकार हराओ–देश बचाओ, सविधान बचाओं, लोकतंत्र बचाओं के नारे के

साथ देशव्यापी राजनीतिक अभियान के तहत चल रहे जन जागरण अभियान में भाग लिया।

पानीपत में 5, 6, 7 मई को भारतीय कम्युनिस्स्ट पार्टी के देशव्यापी राजनीतिक अभियान के तहत चले अभियान में चावला कालोनी, राजीव कालोनी, शिवनगर, भारत नगर, कुटानी रोड़ तथा राजा खेड़ी, मोहाली, अटावला, हड़ताड़ी, डाहर आदि गांवों में कई नुक्कड़ मीटिंग की गई जिन्हें पार्टी के राज्य सचिव दरियाव सिंह कश्यप, जिला सचिव पवन कुमार सैनी, रामरतन एड़वोकेट, मामचंद सैनी, जमशेद राणा आदि ने संबोधित किया। कम्युनिस्ट नेताओं ने कहा कि भाजपा सत्ता का खुलेआम दुरुपयोग कर रही है और महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को एफआईआर होने के बावजूद गिरफ्तार नही कर रही। कम्युनिस्ट नेताओं ने भाजपा सरकार द्वारा अपनाई जा रही कारपोरेटपरस्त एवं सम्प्रदायिक नीतियों की घोर निंदा करते हुए देश, संविधान, लाकतंत्र बचाने के लिए देश और प्रदेश से भाजपा सरकार हटाने पर जोर दिया।

कम्युनिस्ट नेताओं ने आजादी के आंदोलन में भारतीय कम्युनिस्स्ट पार्टी की भूमिका और आजाद भारत में रोजगार, शिक्षा, बड़े उद्योग के विकास और सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना में दिये गए योगदान की भी चर्चा की । इन दिनों चले जन जागरण अभियान में शीशराम तोमर, जूनेद राणा, भूपेन्द्र कश्यप, रुपेश सैनी, हरपाल सिंह कश्यप, भान सिंह अटावला, नरेन्द्र देशवाल, चंद्रभान निम्बरी, रामबीर कश्यप आदि भी शामिल रहे ।

सिरसा

सिरसा के रानिया उपमंडल के प्रसि) गांव करीवाला से 6 मई को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के देशव्यापी राजनीतिक अभियान के तहत जन जागरण अभियान शुरु हुआ । ग्राम सचिवालय में एक सभा आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ भाकपा नेता रेसम सिंह संधु ने की । सभा को संबोधित करते हुए सी.पी.आई. के राज्य कंट्रोल कमीशन के चेयरमैन स्वर्ण सिंह विर्क ने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार सम्प्रदायिक उन्माद फैलाकार विभाजनकारी व मजदूर, किसान विरोधी और कारपोरेटपरस्त नीतियां अपना कर देश के आत्मनिर्भर आर्थिक विकास को कमजोर कर रही है ।

उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की फौज में प्रतिवर्ष एक करोड़ की बढ़ोतरी हो रही हैं और सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही हाल में देश में 34 करोड़ पढ़े–लिखे युवा बेरोजगार हैं । उन्होंने कहा कि आज देश में संविधान, लोकतंत्र खतरे में है । इसलिए संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संसदीय जनतंत्र व समाजवाद के उच्च आदर्शो को बचाने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा व उसकी सहसोगी पार्टियों को हराने के लिए धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, प्रगतिशील व देशभक्त शक्तियों का एक व्यापक मोर्चा कायम करना अति आवश्यक है ।

इस मौके पर प्रीतपाल सि), बलराज बणी, हरजिन्द्र भंगु ने बढ़ती महंगाई, अमीरी व गरीबी के बीच गहरी होती जा रही खाई, दलितों–महिलाओं व अल्पसंख्यकों पर बढ़ रहे हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की । कम्युनिस्ट नेताओं ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अभी तक राज्य में हुई भयंकर ओलावृष्टी व बेमौसमी बरसात से खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं दिया लेकिन हरियाणा में को–आप्रेटिव सोसाटियों से गरीब किसानों द्वारा लिये गए कर्ज पर फिर से 7 प्रतिशत ब्याज कर दिया है ।

करीवाला से शुरु हुए सी.पी.आई के प्रचार जत्थे ने दमदमा, जगजीत नगर, हरी पुरा, संत नगर, जीवन नगर, संतावली और नकोड़ा में दर्जन से अणिक सभाओं व नुक्कड़ मीटिंगों को संबोधित किया । प्रचार जत्थे में वक्ताओं के साथ–साथ हरदेव सिंह, दलजीत सिंह काहलों, पाल सिंह, पाला सिंह चीमा, सुरजीत सिंह सरपंच, हाकम सिंह विर्क, धर्मपाल नथोर, गुरनाम सिंह, जोगेन्द्र सिंह दमदमा आदि शामिल रहे ।

7 मई को रानिया एरिया के तलवाड़ा, मिर्जापुर, टोपनिया, अमृतसर कला, मुढ़ी मेढ़ी, मोजु खेड़ा, मुढ़ी मेढ़ी चौक, पाल पट्टी, शैखू खेड़ा, रत्ता खेड़ा, कुत्ताबढ़ गांवों में सी.पी.आई. का राजनीतिक अभियान चलाया गया । इस दौरान एक दर्जन से अधिक नुक्कड़ मिटिंग आयोजित की गई जिन्हें डाक्टर सुखदेव सिंह जम्मू, प्रीतपाल सि), हरदेव सिंह जोश, डाक्टर देव नागरा सहित अन्य ने संबोधित किया । प्रचार जत्थे में रेसम सिंह, अरमान गिल, गुरनाम सिंह करीवाला, बुटा सिंह दमदमा, जसबीर रंधावा, सुमेर गिल आदि शामिल रहे ।

8 मई को रानिया उपमंडल के बणी नथोर, बचेर, वाहिया, सैनपाल, मत्तुवाला, साढ़े वाला, ढढियावाली आदि गांवों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के देश व्यापी राजनीतिक अभियान के अंतर्गत नुक्कड मीटिंगें की और पर्चे बांटे गये । इन मीटिंगों को स्वर्ण सिंह विर्क, डाक्टर सुखदेव सिंह जम्मू, प्रीतपाल सि), बलराज बणी, हरदेव सिंह जोश आदि ने संबोधित किया । कम्युनिस्ट नेताओं ने राज्य व केन्द्र में सत्तारुढ़ भाजपा गठबंधन की सरकारों की जनविरोधी नीतियों की जनता को जानकारी दी । वक्ताओं ने सी.पी.आई. के इतिहास पर विस्तार से चर्चा की और पार्टी द्वारा आजादी के आंदोलन में दी गई कुरबानियों तथा आजादी के बाद देश के चौतरफा विकास में पार्टी के योगदान की व्याख्या की । प्रचार जत्थे में रेसम सिंह करीवाला, जसबीर सिंह रंधावा, डाक्टर देव नागरा, बुटा सिंह, हाकम सिंह विर्क, कश्मीर सिंह, रतन सिंह रंधावा आदि शामिल रहे ।

सिरसा

उत्तराखंड

यमुनानगर

बिलासपुर में 5, 6, 7 मई को सी.पी.आई. का जन जागरण अभियान पार्टी की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य एवं पार्टी के जिला सचिव धर्मपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में चलाया गया । इन दिनों में बिलासपुर के बाजारों, चौहराहों एवं कालौनियों में नुक्कड़ मीटिंगें की गई । जिन्हें धर्मपाल सिंह चौहान, अरुण कुमार शक्करवाल, गुरभजन सिंह, राम करण शर्मा, फकीर चंद आदि ने संबोधित किया । कम्युनिस्ट नेताओं ने कहा कि भाजपा सत्ता का खुलेआम दुरुपयोग कर रही है और अपने चहेते कारपोरेट घरानों को सार्वजनिक सम्पति कोड़ियों के भाव दे रही है । इसके साथ ही महिला पहलवानों का योन उत्पीड़न करने वाला भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और महिला कोच के साथ छेड़छाड़ करने का आरोपी मंत्री संदीप सिंह खुले घूम रहे हैं और भाजपा इन्हे बचाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर रही है । कम्युनिस्ट नेताओं ने भाजपा सरकार द्वारा अपनाई जा रही कारपोरेटपरस्त एवं सम्प्रदायिक नीतियों की घोर निंदा करते हुए देश, संविधान, लोकतंत्र बचाने के लिए देश व प्रदेश से भाजपा सरकार को हटाने पर जोर दिया ।

कम्युनिस्ट नेताओं ने आजादी के आंदोलन में भारतीय कम्युनिस्स्ट पार्टी की भूमिका और आजाद भारत में रोजगार, शिक्षा, बड़े उद्योग के विकास और सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना में दिये गए योगदान की भी चर्चा की । जन जागरण अभियान के साथ–साथ बाजारों में फंड संग्रह अभियान भी चलाया और इस दौरान दुकानदारों व आम नागरिकों से 30 हजार रुपये से अधिक फंड एकत्रित किया । प्रचार जत्थो में प्रवीन शक्करवाल, नीरज चौहान, विपिन बरार, प्रवीन चौहान, विजयपाल सिंह आदि कम्युनिस्ट नेताओं ने भाग लिया ।

नरवाना

जींद जिले के नरवाना उपमंडल में 5, 6, 7 मई को भारतीय कम्युनिस्स्ट पार्टी के देशव्यापी राजनीतिक अभियान के तहत जन जागरण अभियान चलाया गया । इस दौरान बेलरखा, उझाना, गढ़ी दातासिंह वाला, रेवर, पीपलथा, भाणा ब्रह्मणान, धरोदी, बिधराना, ढ़ाकल आदि गांवों और नरवाना अनाज मंडी में नुक्कड़ मीटिंगें की गई और हजारों पर्चे बांटे गए । इन मीटिंगों में सी.पी.आई. की हरियाणा राज्य कार्यकारिणी के सदस्य एवं जिला सचिव मनीराम बेलरखा, सतपाल सरोवा, भीमसिंह सिंहमार, ओमप्रकाश शर्मा, अमरजीत सिंह, मिहासिंह, जोगेन्द्र सिंह आदि ने भाजपा सरकार द्वारा अपनाई जा रही जन विरोधी, देश विरोधी, संविधान विरोधी नीतियों की व्यापक चर्चा की और भारतीय कम्युनिस्स्ट पार्टी की देश के विकास और एकता–अखंडता की रक्षा में दिये गए योगदान, बलिदानों की विस्तार से चर्चा की । कम्युनिस्ट नेताओं ने नागरिकों से सी.पी.आई को तन–मन–धन से सहयोग करने की अपील की ।

पंचकुला

6 व 7 मई को पंचकुला के सेक्टर 25 तथा रामगढ़ और बरवाला में सी.पी.आई. के जिला सचिव एम.सी. बासिया के नेतृत्व में जन जागरण अभियान चलाया और नुक्कड़ मीटिंगें की तथा नागरिकों में हजारों पर्चे बांटे । प्रचार जत्थे में एम.सी.बासिया, भगत राम, हरबंश सिंह, अशोक कुमार, अरविंद, निखिल आदि शामिल रहे ।

कैथल

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के देशव्यापी राजनीतिक अभियान भाजपा सरकार हटाओ, संविधान, लोकतंत्र, देश बचाओं के तहत कैथल के बरोट, बंदराना, टीक, ग्योंग, क्योडक और कैथल शहर की अफगान पट्टी में डोर टू छोर अभियान चलाया गया । इस दौरान भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गौरवशाली इतिहास बारे दो अलग–अलग पर्चे बांटे गए और कुछ नुक्कड़ मीटिंगें भी की गई । प्रचार जत्थे का नेत्त्व पार्टी के जिला सचिव महेन्द्र सिंह तंवर ने किया और हरभजन सिंह बरटा, ईशम सिंह तंवर, शेरखान, पवन कुमार आदि कम्युनिस्ट नेता जत्थे में शामिल रहे ।

सारण (बिहार)

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मकेर अंचल कमेटी की ओर से मई दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी हटाओ, देश बचाओ, नया भारत बनाओ के नारे के साथ प्रखंड के फुलवरिया, चकिया, सुल्तानगंज, नंदन कैतुका, आदि दर्जनों ग्रामों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव रामबाबू सिंह के नेतृत्व में पदयात्रा की गई और और भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामियों का पर्दाफाश किया गया।

पदयात्रा के दौरान कई जगहों पर यथा फुलवरिया में आमसभा का आयोजन किया गया जिसे संबोधित करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता रामबाबू सिंह ने कहा कि मोदी सरकार को देश के विकास की चिंता नहीं है, उसे सिर्फ अदानी, अंबानी जैसे

शेष पेज 10 पर...

अयोध्या प्रलेस का जिला सम्मेलन

'वर्चस्व के दौर में साहित्य की भूमिका'

आर.डी. आनन्द

फैजाबाद, 30 अप्रैल 2023: फैजाबाद में अयोध्या प्रगतिशील लेखक संघ जिला इकाई अयोध्या के तत्वावधान में 'वर्चस्व के दौर में साहित्य की भूमिका' विषय पर प्रेस क्लब फैजाबाद में एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ कवि स्वप्निल श्रीवास्तव तथा संचालन अशोक कुमार तिवारी ने किया।

सर्वप्रथम विषय पर बोलते हुए डॉ. रघुवंशमणि ने कहा कि 1936 मे मुंशी प्रेमचन्द ने कहा था 'साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है'। इसी सन्दर्भ में उन्होंने बताया कि अच्छी सत्तायें कम से कम शासन करती हैं लेकिन आज सत्ता का वर्चस्व बहुत बढ़ा हुआ है जिसे अधिनायकवाद कहा जा सकता है। सत्ता ऐसी होनी चाहिए जहाँ जनतंत्र का मूल्य सर्वोपरि हो और जनता के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो लेकिन जनतंत्र अधिनायकवादियों की दासी हो चुका है तथा जनता डरी हुई है। जनमत यह है कि जनता को लिखने, पढ़ने व बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ तक कि लेखकों और कवियों को लिखने के विषय और लक्ष्य नियंत्रित कर दिये गये हैं। वर्तमान में सत्ता पुलिस, मिलिट्री, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अपने हित में प्रयोग कर रही है। जनतंत्र व लोकतंत्र को धीरे–धीरे समाप्त किया जा रहा है। सत्ता मनमानी पर उतर आयी है। यहाँ तक कि पुलिस नियंत्रण में हत्यायें सुनियोजित की जा रही हैं। सांस्कृतिक वर्चस्व के रास्ते राजनैतिक वर्चस्व स्थापित किया जा रहा है। इस दौर में प्रतिरोध का जन्म लेना नितान्त आवश्यक है। डॉ. रघुवंशमणि ने ब्रेख्त, ग्राम्शी, एडोर्नो, नोमचोम्श्की को आधुनिक विचारधाराओं के रूप में रेखांकित किया।

तत्पश्चात सुश्री विनीता कुशवाहा ने वर्चस्व को व्याख्यायित करते हुए कहा कि जब किसी समूह का अन्य समूहों के ऊपर राजनीतिक, वैचारिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दबदबा मौजूद हो तो इसे वर्चस्व कहते हैं। वर्तमान में भारतीय सत्ता उक्त के अनुसार भारतीय जनमानस पर जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं नाजीवादी तरीके से दबाव बनाये हुए है। अमूमन भारतीय पृष्ठभूमि में चार–पाँच हजार वर्ष पूर्व से एक विशेष धर्म एवं संस्कृति का वर्चस्व रहा है जिनकी वजह से स्त्रियों को अर्धनग्न अवस्था में रहना पड़ता था, मनुस्मृति में ऐसी संविधि तैयार की गयी जिसमें स्त्री और शूद्र को शिक्षा और सम्पत्ति से वंचित कर दिया गया था। बहुत पहले बुद्ध ने इनकी संस्कृति और वर्चस्व को चुनौती दी थी। तत्पश्चात कबीर, रैदास, दादू नानक इत्यादि ने बिना अपने जीवन का मोह किये इनकी संस्कृतियों के विरूद्ध दोहे व चौपाइयों को गा कर सामाजिक जागरूकता पैदा की।

विनीता ने आह्वान कि साहित्यकर्मियों बिना भयभीत हुए अपनी जान की बाजी लगाकर सत्ता के विभिन्न वर्चस्वों के विरूद्ध क्रांतिकारी साहित्य लिखना व गाना चाहिए। आज के दौर में वर्चस्व का प्रतिरोध ही साहित्य का धर्म है। इसी क्रम में डॉ. विशाल श्रीवास्तव (जलेस) ने ब्रेख्त को उद्धृत करते हुए कहा क्या जुल्मतों के दौर में गीत गाये जायेंगे? हा जुल्मतों के दौर में भी गीत गाये जायेंगे। उन्होंने भी कहा कि साहित्य का धर्म है कि वह वर्चस्व का विरोध करे। आगे विशाल श्रीवास्तव ने कहा कि आखिर वर्चस्व हुआ ही क्यों? अपने प्रश्न के जबाब में उन्होंने बताया कि बहुसंख्यकवादी संस्कृति अनेक संस्कृतियों के मध्य वर्चस्व स्थापित कर ही लेती है। एडोर्नो की पुस्तक सांस्तिक उद्योग के अंश को कोड करते हुए कहा कि राजनैतिक वर्चस्व सांस्कृतिक वर्चस्व के पीछे–पीछे आता है और सांस्कृतिक वर्चस्व राजनैतिक वर्चस्व से अधिक खतरनाक होता है। विशाल श्रीवास्तव ने सांस्कृतिक और राजनीतिक वर्चस्व के विरूद्ध एक व्यापक जन प्रतिरोध की अपेक्षा में अपना वक्तव्य खत्म किया। विषय को आगे बढ़ाते हुए डॉ. अनिल कुमार सिंह ने कहा कि तुलसीदास जी का रामचरितमानस इन वर्चस्वादियों का सांस्कृतिक प्रोजेक्ट है। मीडिया न्यूज चैनल, अखबार, पुलिस, मिलिट्री एवं न्यायिक व्यवस्था पर वर्चस्ववादियों का कब्जा है। ये धर्म व संस्कृति द्वारा जनता पर हमलावर हैं।

अन्त में, प्रलेस सचिव आर.डी. आनन्द ने साहित्य की भूमिका वर्चस्व के दौर में क्या हो, विषय पर बोलते हुए कहा कि साहित्य जीवन की आलोचना है बल्कि इससे भी आगे साहित्य अपने अवयवों के माध्यम से व्यवस्था और सत्ता के हर प्रतिबन्धों, वर्चस्वों एवं अधिनायकत्व के विरूद्ध जोरदार हुंकार एवं लयात्मक सुर भी है। आनन्द ने कबीर के एक दोहे 'कबिरा खड़ा बाजार में लिये लुकाठी हाथ, जो घर फूंके आपनो चलै हमारे साथ' को क्रांतिकारी साहित्य के माध्यम से साहित्यकारों की भूमिका सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि कबीर आज से लगभग 500 साल पहले हिन्दू और मुस्लिम संस्कृति एवं उनके वर्चस्ववादी दृष्टिकोण को चुनौती देते हुए चौपालों में गाते फिरते थे कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोऊ न पूजै जाकर पीसा खाय संसार 2– कांकर पाथर जोरि कै मस्जिद लई बनाय ता चढ मुल्ला बाग दे का बहरा भया खुदाय? आनन्द ने स्वतंत्रता संग्राम के समय बंकिमचन्द्र चटर्जी द्वारा लिखित वन्देमातरम, रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा गाया गया 'सरफरोशी की तमन्ना' अशफाक उल्लाह खां द्वारा लिखित कस ली है कमर अब तो, कुछ कर के दिखायेंगे आजाद ही बोलेंगे या सर ही कटा देगें। मो. इकबाल द्वारा लिखित कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, मैथिलीशरण गुप्त द्वारा लिखित जिनको न निज गौरव न निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा बुन्देले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जयशंकर प्रसाद हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती आदि का जिक्र किया। इसी क्रम में जिन कवियों की कवितायें जनप्रतिरोध के रूप में जनता के जुबान पर आयी, जैसे कवियों शिवमंगल सिंह सुमन, राम नरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, राधाकृष्णदास, श्रीधर पाठक, माधव प्रसाद शुक्ल, नाथूराम शर्मा शंकर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, अज्ञेय प्रतापनारायण मिश्र, पं. अम्बिकादत्त व्यास, बाबूराम किशन वर्मा, आलोक धन्वा, रामशंकर यादव विद्रोही, आर चेतन क्रान्ति, अमित तिवारी, अशद जैदी, अवतार सिंह पाश, गोरख पाण्डेय, दुष्यंत कुमार तथा अदम गोण्डवी आदि क्रान्तिकारी कवियों का उल्लेख किया। आर डी आनन्द ने संक्षेप में कहा कि इन तमाम कवियों की तरह वर्तमान में आधुनिक कवियों को एक विश्व दृष्टिकोण के साथ संवेदना और यथार्थ को शब्दांकित करते हुए वर्चस्व के विरूद्ध सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रतिरोध को एक सामूहिक नेतृत्व में चौतरफा फैलाना होगा। आज यदि हम वर्गीय एकता स्थापित न कर सके तो इन वर्चस्ववादियों के धुर दबाव में हमें धूल चाटना पड़ेगा इसलिए मुंशी प्रेमचन्द के उस वाक्य साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है को चरितार्थ करते हुए कबीर के आहवान कबिरा खड़ा बजार में का अनुशरण करते हुए नेतृत्व को जन्म देना होगा।

कार्यक्रम के अन्तिम दौर में काव्य पाठ भी किया गया जिसका संचालन मुजम्मिल फिदा ने किया जिसमें याकूब खान, विशाल श्रीवास्तव, मोतीलाल तिवारी, बौद्ध राम दुलारे, जसवन्त अरौडा, विनीता कुशवाहा, आर.डी. आनन्द, रघुवंशमणि, रामजीत यादव बेदार स्वप्नि श्रीवास्तव, सत्यभान सिंह ने भाग लिया ।

संगोष्ठी में प्रमुख रूप से रामतीर्थ पाठक, अयोध्या प्रसाद तिवारी, शारदा आनन्द, यशोदा सिंह, कुमकुम भाग्या, मिन्दिला चौधरी, रामनयन मिश्र, सम्पूर्णानन्द बागी, श्रीप्रकाश सिंह, कुमार वैभव, रामप्रसाद, जगेसर प्रसाद, अखिलेश पाल, बालकृष्ण यादव, विनीत मौर्य, पूनम बौद्ध, राम सुरेश शास्त्री, सुमन गुप्ता, डॉ. मुकेश आनन्द, गुड्डू कुमार, सूर्यकान्त पाण्डेय, शिवम पाण्डेय, अमिताभ श्रीवास्तव, रामजी यादव ने भाग लिया। कार्यक्रम के संयोजक अयोध्या प्रसाद तिवारी ने आये हुए लोगो के प्रति आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। अन्त मे साहित्यकार रंजीत गुहा ने निधन पर दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।

जारी है भाकपा का देशव्यापी जन जागरण...

पेज 9 से जारी...

पूंजीपतियों के विकास की चिंता है और उनकी संपत्ति दिन दूना रात चौगुना बढ़ती जा रही है बेकारी, महंगाई, आसमान छू रही है, किसान मजदूर कंगाल हो रहे हैं, संविधान, आजादी, संप्रदायिक सद्भाव खतरनाक मुहान पहुंच गया। सरकारी संस्थानों का निजीकरण अवैध गति से जारी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को हराना जनहित में समय की मांग है जिस दिशा में हमें तेज गति से बढ़ना है।

सभा को महात्मा जी, मोहन राय, रामदास राय सुरेंद्र राय, जयपाल राय, लालबाबू राय, मुख्तार राय, पुनकाल राम, शिवपूजन शाह ने संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी सरकार को 2024 के चुनाव में रहने का आह्वान किया।

पूर्वी दिल्ली

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय फैसले के तहत मोदी हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ के नारे को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूर्वी दिल्ली ने 10000 हैंडबिलों के साथ गली गली और मुहल्ले मुहल्ले तथा मार्किटो में जनता से संपर्क किया और फण्ड भी एकत्र किया।

जनता से संपर्क अभियान14 अप्रैल 2023 डॉ. भीम राव अम्बेडकर जी की जयंती के पावन अवसर से जारी किया गया। यह अभियान 20 मई तक जारी रहेगा। मोदी हटाओ, संविधान बचाओ के अभियान में रमेश चन्द, राजेश कुमार तिवारी, गिरी राम, शशि कुमार गौतम, प्रिया डे, पूनम, कन्हैया लाल और डॉ. केहर सिंह शामिल रहे।

बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 14 अप्रैल 2023 से 15 मई 2023 संपूर्ण भारत भर में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी आभियान के तहत 05 मई 2023 को वार्ड नंबर 42 देवरीडीह बिलासपुर में शाम 6 बजे से कार्ल मार्क्स और गौतम बुद्ध जन्म जयंती पर आमसभा कर लोगों को जागरूक किया गया। सभा की अध्यक्षता वरिष्ठ भाकपा नेता कांशीराम ठाकुर ने की।

सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स और गौतम बुद्ध की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित कर सभा की शुरुआत की। सभा को नौजवान सभा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत शर्मा ने संबोधित करते हुए देश में बढ़ती बेरोजगारी को नौजवानों के भविष्य के लिए खतरनाक बताया। साथ सार्वजनिक इकाइयों का निजीकरण किए जाने पर केंद्र पर निशाना साधा एवं बेरोजगारी भत्ता और राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में लम्बे समय से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिको को नियमित करने की राज्य सरकार से मांग की। एआईएफएफ के राज्य परिषद सदस्य संत निराला ने अपनी बात रखते हुए केंद्र सरकार को महंगाई बढ़ाने का जिम्मेदार ठहराते हुए जीवन उपयोगी आवश्यक दाल, चावल, आटा, कपड़ा व अन्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाने पर केंद्र सरकार की घोर निन्दा की। एच डी पाइक ने महंगाई, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार की जनविरोधी छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज करने का आह्वान किया।

भाकपा जिला सचिव पवन शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए किसानों और मजदूरों को एकजुट होकर केंद्र सरकार को कारपोरेट घरानों की कठपुतली करार दिया। केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए देश की अर्थव्यवस्था पर चिंता जाहिर की साथ ही कारपोरेट घरानों के टैक्स माफी पर सवाल उठाए और देश में फैले जातिवाद, संप्रदायवाद, गैर बराबरी, धार्मिक उन्माद, बढ़ने पर केंद्र सरकार की फांसीवादी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही वर्षो से जमीन पर काबिज लोगों को पट्टा देने की मांग की। आमसभा में मुख्य रूप से पवन शर्मा, एच डी पाइक, दिलीप धूरी, विक्रम शर्मा, पुनाराम धूरी, संत निराला, गोकुल चौहान, पावेल शर्मा, साधु राम धूरी, मंतराम धूरी, रवि शर्मा, फगनी बाई धूरी, नरेंद्र धूरी, श्यामलाल नेताम, अमरिका बाई वर्मा, सुकुवरा बाइ, नन्ही साहु, बूंद कुवर, ढेलिया बाई, मनसाराम ठाकुर, मनिहार मानिकपुरी, रवि मानिकपुरी, फुलवा बाई, रामकली बरगाह, पद्मा बाई भारी संख्या में महिला एवं पुरुष मौजूद थे।

अमर्त्य सेन का उत्पीड़न

आर.एस. यादव

यह देखकर हैरत होती है कि हमारे देश में अमर्त्य सेन जैसे विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति का उत्पीड़न किया जा रहा है। अमर्त्य सेन एक महान अर्थशास्त्री हैं। उन्हें 1998 में अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार, नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1999 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वह एक वयोवृद्ध व्यक्ति हैं। उनका जन्म से ही महाकवि रवीन्द्रनाथ टेगौर और विश्व भारती से संबंध रहा है। उनके नाना क्षितिज मोहन सेन रवीन्द्रनाथ टेगौर के सबसे करीबी सहयोगी थे। अमर्त्य सेन का जन्म ही विश्व भारती में हुआ। उनका नामकरण भी रवीन्द्रनाथ टेगौर ने किया। विश्व भारती परिसर में उनका पैतृक मकान है। 3 नवंबर 1933 को उनके जन्म के बाद पिता आशुतोष सेन बेटे को गुरूदेव टेगौर के पास ले गए। गुरूदेव ने शिशु को भरपूर स्नेह और दुलार किया और कहा, ''यह असामान्य बालक है। बड़ा होकर असाधारण बनेगा और दुनिया से जाने के बाद भी इसका नाम अक्षुण्ण रहेगा, इसलिए इसे ''अमर्त्य'' नाम से पुकारा जाना चाहिए''।

अमर्त्य सेन ने बचपन में, 1943 में, बगाल में पड़े अकाल के दौरान ढाका में अपने घर के सामने एक–एक दाने के लिए गिड़गिड़ाते, भूख से दम तोड़ते लोगों को देखा था। बड़े होकर उन्होंने गरीबी और भूख पर ही काम किया और उनके उसी काम के लिए उन्हें अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार मिला।

सचमुच ही टेगौर की भविष्यवाणी सही साबित हुई। अमर्त्य सेन ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। परंतु न जाने क्यों भारत सरकार उन्हें परेशान करने पर आमादा है।

विश्व भारती विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उन पर आरोप लगा दिया कि उनके पैतृक मकान में कुछ ''अतिक्रमित भूमि'' है। उन्हें कहा गया कि वह इस अतिक्रमित भूमि को खाली करें। परंतु पश्चिम बंगाल की सरकार ने कहा है कि उनके मकान में कोई अतिक्रमित भूमि नहीं है। इसके बावजूद विश्व भारती ने उन्हें 6 मई तक इस तथाकथित ''अतिक्रमित भूमि'' को खाली करने का नोटिस दिया है।

यह नहीं माना जा सकता कि अमर्त्य सेन जैसे प्रख्यात व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई विश्व भारती के उपकुलपति या किसी अन्य अधिकारी की पहल पर की जा रही है। इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि नोबल पुरस्कार और भारत रत्न से सम्मानित अमर्त्य सेन जैसे व्यक्ति के साथ इस तरह की कार्रवाई विश्व भारती विश्वविद्यालय के स्तर पर किसी की पहल पर की जाए। तो फिर यह हिमाकत कौन कर रहा है? कौन है जो भारत रत्न अमर्त्य सेन के इस प्रकार उत्पीड़न पर आमादा है?

विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा अमर्त्य सेन पर भूमि के तथाकथित ''अतिक्रमण'' के संबंध में आरोप लगाने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार के इस स्पष्टीकरण के बाद मामला समाप्त हो जाना चाहिए था कि अमर्त्य सेन या उनके पिता ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है।

यदि थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि आज से 80 साल पहले जब विश्व भारती ने उनके पिता को वहां आवास के लिए जमीन दी थी और उनके उस पैतृक मकान में, विश्व भारती के आरोप के अनुसार, उससे 13 डिस्मल जमीन

अधिक है, तो क्या यह उचित नहीं था कि इस तरह आरोप लगाने, उत्पीड़न करने और लगभग 90 वर्ष के वयोवृद्ध भारत रत्न अमर्त्य सेन को जानबूझ कर परेशान करने के बजाय उस अतिरिक्त जमीन को रेगुलराईज कर दिया जाता?

यह मामला समाचार पत्रों में आ रहा है। दुनिया भर में भारत की बदनामी हो रही है कि भारत अपने एक सबसे सम्मानित व्यक्ति, विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार, नोबल पुरस्कार और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति के साथ किस तरह का सलूक कर रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नोटिस में यह बात नहीं आई है? प्रधानमंत्री विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं। ऐसा नहीं माना जा सकता कि जो बात सारी दुनिया के नोटिस में आ गई है, वह भारत के प्रधानमंत्री के नोटिस में नहीं आई हो। तो फिर वह चुप क्यों हैं? कहीं इसलिए तो नहीं कि सब कुछ उन्हीं के इशारे पर हो रहा है?

विश्व भारती ने 13 डिस्मल जमीन की बेदखली के बारे में उन्हें पत्र में लिखा था :''रिकॉर्डो और भौतिक तौर पर सर्वे/ निशानदेही से पता चला है कि आपने विश्व भारती के प्लाट नं. मौजा सुरूल के प्लाट नं. 1900/2487 में 13 डिस्मल जमीन पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। .....यह उस125 डिस्मल जमीन से फालूत है जो आपके स्वर्गीय पिता आशुतोष सेन को 27 अक्टूबर 1943 में लीज पर दी गई थी और जो 2006 में आपके नाम की गई। आपसे अनुरोध है कि इस 13 डिस्मल जमीन को शीघ्र से शीघ्र से विश्व भारती के हवाले कर दें।''

बाद में उन्हें नोटिस दिया गया कि इस 13 डिस्मल जमीन को 5 मई तक खाली कर दिया जाए अन्यथा, ऐसा जरूरी हुआ तो, जबरन छीन ली जाएगी।

भूमि के अतिक्रमण/ अवैध कब्जे के आरोप को अमर्त्य सेन कई बार गलत ठहरा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि विश्व भारती ने 1.25 एकड़ जमीन उनके पिता को लीज पर दी थी और जिस 13 डिस्मल जमीन के बारे में विवाद किया जा रहा है, उसे उनके पिता ने विश्व भारती से खरीदा था। इसके संबंध में उनके पास दस्तावेजी सबूत हैं।

प्रश्न उठता है कि भारत रत्न अमर्त्य सेन के साथ इस तरह की बदसलूकी क्यों की जा रही है? क्या इसलिये कि वह नरेन्द्र मोदी सरकार की गलत नीतियों एवं गलत कार्यो की आलोचना करते रहे हैं?

अमर्त्य सेन बेलाग और सुस्पष्ट तरीके से बात करने के लिए जाने जाते हैं। एक साक्षात्कार में मोदी सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था कि ''मोदी सरकार दुनिया की सबसे घटिया सरकारों में एक है''। वह इस दृष्टिकोण पर क्यों पहुंचे इसका खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार ''अपने स्वयं के लोगों के साथ घटिया दर्जे का सलूक करती है'' और साथ ही जोड़ा कि ''सरकार का रिकॉर्ड सचमुच बड़ा भयानक रहा है''।

उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के प्रति मोदी सरकार का बर्ताव और यह हकीकत कि संसद के किसी भी सदन में उसका कोई मुस्लिम संसद सदस्य नहीं है, एक ''अस्वीकार्य बर्बरता'' है।

उन्होंने कहा कि ''यह शब्द ''बर्बरता'' मेरी जुबान पर आता है क्योंकि यह सरकार न केवल जालिम और गलत है बल्कि यह लोगों की जिंदगी को पूरी तरह संकटपूर्ण बनाती है और भारत की संस्कृति को सीमित करती है''।

दिसंबर 2019 में फ्रांस के समाचारपत्र '' ले मोंड'' को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने अपनी एक टिप्पणी की व्याख्या करते हुए कहा कि ''यह (भारत सरकार) इस शब्द के संकीर्णतम अर्थ में सांप्रदायिक है, मुस्लिमों पर हमले कर रही है और इस विचार का प्रचार कर रही है कि हिन्दू एक राष्ट्र बनाते हैं''।

उस साक्षात्कार के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि ''भारत हमेशा एक बहु–नृवंशीय (मल्टी एथनिक) देश रहा है। जब उनसे पूछ गया कि क्या वह समझते हैं कि भारत में मुस्लिम विरोधी पूर्वाग्रह बढ़ रहा है और मुस्लिम दोयम दर्जे के नागरिक बनते जा रहे हैं और क्या वह इससे चिंतित है तो उन्होंने कहा , ''मैं केवल चिंतित ही नहीं हूं , मैं भयाक्रांत हूं कि विभिन्न घटकों के साथ एक राष्ट्र अचानक अनर्थकारी अलगाव की स्थिति में आ गया है''।

उन्होंने आगे कहा कि ''अल्पसंख्यकों के साथ बदसलूकी राष्ट्र की प्रमुख गलतियों में से एक है''। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ यह बर्ताव ''देश के इतिहास और वर्तमान का भयानक पतन और विध वंस'' है।

जब उनसे इस तथ्य के बारे में पूछा गया कि केबिनेट मंत्री और यहां तक कि मुख्यमंत्री भी मुसलमानों का उल्लेख ''दीमकों'' और ''बाबर की औलाद'' के तौर पर करते हैं और ''अब्बा जान'' का हवाला देकर उन्हें चिढ़ाते हैं और बार–बार उनसे कहते है कि पाकिस्तान चले जाओ तो अमर्त्य सेन ने कहा कि ''यह भाषा भारतीय राष्ट्र की उनकी विकृत समझ का प्रतिबिंब है''।

उन्होंने आगे कहा कि ''वह (मोदी सरकार) नहीं समझते कि एक राष्ट्र का क्या अर्थ होता है''।

मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की भी अमर्त्य सेन ने कई बार आलोचना की है और कहा है कि उनकी नीतियों से देश और देश के लोगों को नुकसान पहुंच रहा है।

2019 में मोदी सरकार के दूसरी बार चुने जाने पर अमर्त्य सेन ने न्यूयार्क टाइम्स में एक लेख में लिखा था कि ''मोदी ने सत्ता पाने में जीत हासिल कर ली है, विचारों के युद्ध में नहीं''। उन्होंने लिखा कि चुनावी अभियान के समय उनकी वाकपटुता में उनके पास अपनी उपलब्धियों के संबंध में कुछ भी कहने को नहीं था, उन्होंने राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और पाकिस्तान से खतरे पर फोकस किया.....जिस तरह 1927 के फॉकलैंड युद्ध ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्ग्रेट थैचर के लिए समर्थन जुटाया था और उनकी लोकप्रियता में नाटकीय वृद्धि हो गई थी, ठीक उसी तरह फरवरी में पाकिस्तान से सीमा पर लड़ाई ने मोदी को चुनावों में जबरदस्त मदद की''।

उन्होंने आगे लिखा कि मोदी के पहले कार्यकाल में बेरोजगारी 45 वर्ष के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई, आर्थिक वृद्धि लड़खड़ा गई, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की पूरी तरह उपेक्षा कर दी गई और लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार में कहीं कोई कमी नहीं आई।

कुछ सामयिक मुद्दे एवं घटनाक्रम

आर.एस. यादव

संविधान का सम्मान नहीं करते भाजपा के नेता

भाजपा और आरएसएस के लोग अकसर दावा करते रहते हैं भारत एक ''हिन्दू राष्ट्र'' है। आरएसएस प्रमुख इस बात को प्रायः दोहराते रहते हैं, जिससे पता चलता है कि भाजपा और आरएसएस के लोग भारत के संविधान की मर्यादा को नहीं मानते और ऐसे दावे करते रहते हैं जो संविधान के विरूद्ध हैं। भारत का संविधान स्पष्ट तौर पर कहता है कि भारत ''एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र'' है। संविधान की इस स्पष्टता के बावजूद यदि कोई दावा करता है कि भारत एक ''हिन्दू राष्ट्र'' है तो वह भारत के संविधान के खिलाफ बोलता है, संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करता है।

आरएसएस के नेता ही नहीं केंद्र सरकार के मंत्री भी इस तरह अनर्गल एवं असंवैधानिक प्रलाप करते रहते हैं। उदाहरणार्थ, 8 मई 2023 को नई दिल्ली में महाराष्ट्र सदन में वार्षिक नारद पत्रकार सम्मान समारोह में बोलते हुए केंद्र के कानून एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल ने कहा कि संविधान का ''बुनियादी ढांचा'' (बेसिक स्ट्रक्चर) हिन्दू राष्ट्र का है। उन्होंने कहा, ''लोग संविधान के बुनियादी ढांचे के बारे में और इस बारे में कि इसे बदला नहीं जा सकता, अकसर चर्चा करते हैं। इस राष्ट्र का बुनियादी ढांचा उस अखंड हिन्दू राष्ट्र का है जो 1192 से पहले था''।

उनका यह कथन न केवल तथ्यात्मक तौर पर गलत है बल्कि मूर्खतापूर्ण भी है। ''1192 से पहले'' की विभाजक रेखा खींचकर आखिर वे कहना क्या चाहते हैं? संभवतः इससे उनका तात्पर्य तत्कालीन भारत के कुछ हिस्सों में मुस्लिम शासन के प्रारंभ से है। क्या वह नहीं जानते कि उस समय भारत आज की तरह एक एकताबद्ध नहीं बल्कि अनेक हिस्सों में खंड–खंड बंटा हुआ देश था?

मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के विरूद्ध जहर उगलते हुए उन्होंने कहा कि ''ऐसे मुसलमान चंद ही हैं जो सहिष्णु हों; और जो सहिष्णु नजर आते हैं वे सार्वजनिक जीवन में रहने, राज्यपाल, उप–राष्ट्रपति बनने के लिए इसे एक ''मास्क'' के तौर पर इस्तेमाल करते हैं''।

उन्होंने कहाः ''सहिष्णु मुसलमान उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। उनकी संख्या हजारों में भी नहीं है। और वह भी उनकी एक रणनीति है। वह रणनीति है कि इस मास्क के साथ सार्वजनिक जीवन में बने रहें। यह तरीका उन्हें राज्यपाल और उप राष्ट्रपति या उपकुलपति भवन तक ले जाता है। परंतु जब वे वहां से रिटायर होते हैं तो अपने मन की बात बोलने लगते हैं।''

इस अवसर पर वह अकेले ही नहीं थे जिन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जहर उगला। उनसे पहले बोलते हुए इन्फॉर्मेशन कमिश्नर उदय महुरकर ने कहा कि ''इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ भारत को संघर्ष करना चाहिए और ऐसी हस्तियों को, जो सहिष्णु हैं जैसे कि अकबर, गले लगाना चाहिए। इस प्रकार, भारत में मोडरेट और सहिष्णु मुसलमानों को गले लगाया जाना चाहिए''। उनके इस कथन में भी यह निहित था कि भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिम आमतौर पर असहिष्णु और कट्टरपंथी हैं।

परंतु उनके बाद बोलते हुए सत्यपाल बघेल ने अकबर के सहिष्णु होने की बात को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अकबर का सहिष्णु होना एक रणनीति थी। उन्होंने कहा कि ''दीन–ए–इलाही'' और ''सुलह–ए–कुल'' भी उसी तरह की रणनीति थी जैसे कि नवरत्नों में हिन्दुओं को शामिल करना। उनकी (जोधाबाई से) शादी भी एक राजनीतिक शादी थी। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके अंतिम शब्द थे ''या अल्लाह''।''

केंद्र के एक मंत्री के दिमाग में इस तरह की सांप्रदायिकता का होना अत्यंत निंदनीय है। क्या उनसे नहीं पूछा जाना चाहिए कि यदि अकबर ने अंतिम सांस लेते हुए ''या अल्लाह'' कहा तो उसमें क्या गलत था और उन्हें उससे क्या तकलीफ है?

अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के अमरीकी कमीशन द्वारा भारत को एक ''खासतौर पर चिंता के देश'' का नाम देने की सिफारिश

अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के अमरीकी कमीशन (यूएससीआरआईएफ– यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम) ने लगातार चौथी बार अमरीकी सरकार से कहा है कि भारत को एक ''खासतौर पर चिंता के देश'' का नाम दिया जाना चाहिए। 1 मई 2023 को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यूएससीआरआईएफ ने ईरान और पाकिस्तान समेत 12 देशों को फिर से ''खासतौर पर चिंता के देश'' का नाम देने की सिफारिश की है।

यूएससीआरआईएफ की 2023 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का ''बदतर होना जारी रहा''। रिपोर्ट के अनुसार, ''पूरे वर्ष भर केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर भारत सरकार ने धार्मिक तौर पर भेदभाव करने वाली नीतियों को बढ़ावा दिया और लागू किया जिनमें धार्मिक धर्मान्तरण, अंतर–धार्मिक शादियों, हिजाब पहनने और गोहत्या जैसे मामलों में बनाए गए कानून शामिल है। इन कानूनों से अल्पसंख्यकों पर नकारात्मक असर पड़ा है।

रिपोर्ट के भारतीय हिस्से में यूएससीआरआईएफ ने कहा है कि भारतीय संविधान में देश को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र के तौर पर स्थापित किया है और उसमें ऐसे प्रावधान है जो धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ''इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के बावजूद भाजपा नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर ऐसी नीतियों को सुसाध्य बनाया और समर्थन दिया जो अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर करती हैं''। रिपोर्ट कहती है कि सरकार ने ''आलोचनात्मक आवाज–खासतौर पर धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनका समर्थन एवं उनकी वकालत करने वालों की आवाज को दबाना –कुचलना जारी रखा है जिसमें निगरानी रखने, उत्पीड़न करने, संपत्ति का ध्वंस करने और यूएपीए के अंतर्गत गिरफ्तार करना और फॉरेन कन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत गैर–सरकारी संगठनों को निशाने पर लेने जैसी बातें शामिल हैं''।

रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि अमरीकी कांग्रेस अमरीका–भारत द्विपक्षीय मीटिंगों के दौरान भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के हनन के मुद्दे को उठाए।

यूएससीआरआईएफ ने इस पर निराशा व्यक्त की है कि उसकी सिफारिशों के बावजूद अमरीका के विदेश विभाग ने भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में ''खासतौर पर चिंता के देशों''की सूची में शामिल नहीं किया है।

भारत सरकार ने हर वर्ष की तरह इस बार भी यह कह कर इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया कि यह दुर्भावना से प्रेरित है।

किसानों की मदद नहीं करता फसल बीमा

वर्षा, ओलावृष्टि या अन्य किसी कारण से फसलों के नुकसान होने पर किसानों की मदद करने के लिए बीमा योजना वास्तव में किसानों के बजाय बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने का जरिया बन गई है। फसलों को नुकसान होने पर मुआवजा हासिल करने के लिए जो प्रावधान किए गए है वह इस तरह के हैं कि उनकी शर्तें और आकलन के तरीके से किसानों को वाजिब मुआवजा नहीं मिल पाता जबकि बीमा कंपनी मालामाल हो जाती हैं। विभिन्न रिपोर्टें हैं जो बताती हैं कि गत वर्षों में जब अलग–अलग राज्यों में फसलें बड़े पैमाने पर नष्ट हुई, बीमा दावा अदा करने के बाद भी बीमा कंपनियों ने भरपूर मुनाफा कमाया। किसानों को मिलने वाले मुआवजे का यह हाल रहा कि 2019 में मध्यप्रदेश के किसानों को 50 प्रतिशत से अधिक फसल के नुकसान के बाद उनके खातों में दो रुपए से लेकर 200 रुपए तक की राशि अदा की गई। बीमा दावों से फसल नुकसान को पर्याप्त भरपाई न होने से परेशान किसानों ने स्वैच्छिक आधार पर बीमा का प्रीमियम भरना बंद कर दिया। देश के सात राज्यों–आंध्रप्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल में प्रधानंत्री फसल बीमा के लिए राज्य का अंशदान देना बंद कर दिया है जिससे इन राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बंद हो चुकी है।

देश में कृषि से जुड़े किसानों की संख्या लगभग 10.20 करोड़ है। लेकिन वर्ष 2022–23 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकृत किसानों की संख्या मात्र 93.44 लाख रही। नुकसान की तुलना में बहुत कम मुआवजा, समय से भुगतान न होना और राजस्व सर्वे इकाइयों द्वारा भ्रष्टाचार के कारण फसल बीमा पर किसान कोई खास भरोसा नहीं करते।

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का हाल

2019–20 के अंतरिम बजट में सरकार ने बड़े गाजे–बाजे के साथ अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 42 करोड़ लोगों के लिए पेंशन कार्यक्रम–प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की घोषणा की थी। वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा था, ''हमारी सरकार 15 हजार रुपए मासिक तक आय वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बड़ी पेंशन योजना का प्रस्ताव रख रही है। यह पेंशन योजना उन्हें छोटी राशि का योगदान कर 60 वर्ष की आयु से तीन हजार रुपए मासिक पेंशन की गारंटी देगी।

बजट प्रस्ताव के अनुसार, इस पेंशन योजना के तहत 29 साल के कामगार को 60 साल की उम्र तक100 रुपए प्रतिमाह का योगदान देना होगा। वहीं18 वर्ष के कामगार को योजना से जुड़ने के लिए 55 रुपए प्रतिमाह का योगदान देना होगा। सरकारी उतनी ही राशि कामगार के पेंशन खाते में हर महीने जमा करेगी।

पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने ''एक्सप्लैनेशन एंड कमेन्टरी ऑन बजट 2023–23'' शीर्षक से लिखी पुस्तक में दावा किया है, 'श्रमयोगी मानधन योजना (2019–20) के पहले साल में अच्छी संख्या में श्रमिक और कामगार आकर्षित हुए। योजना के तहत 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, 43,64,744 श्रमिक पंजीकृत हुए। लेकिन बाद में योजना को लेकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों की रूचि कम होती गई। वित्तवर्ष 2020–21में केवल 1,30,213 कामगार पंजीकृत हुए और इससे कुल पंजीकृत मजदूरों की संख्या 44,94,864 हो गई।''

उन्होंने लिखा है, ''वित्तवर्ष 2021–22 में 1,61,837 कामगार योजना में पंजीकृत हुए। इससे पंजीकृत कामगारों की संख्या 31 मार्च 2022 तक बढ़कर 46,56,701 तक पहुंच गई। ऐसा लगता है कि उसके बाद जनवरी 2023 से कामगारों ने पंजीकरण रद्द कराना शुरू कर दिया।'' श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के डैशबोर्ड के अनुसार, जनवरी 2023 में 44,00,535 पहुंचने के बाद पंजीकृत कामगारों की संख्या में कमी आई और यह मार्च 2023 में 44,00,535 पर आ गई। वित्तवर्ष 2019–20 के अंतरिम बजट में पांच साल में इस पेंशन योजना से असंगठित क्षेत्र के करीब 10 करोड़ श्रमिकों के जुड़ने की उम्मीद जताई गई थी। (जनसत्ता, 1 मई 2023 की एक रिपोर्ट से)

कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का 175वां वर्ष

''मार्क्सवाद मानव सभ्यता और मानव दर्शन का विकास है। पूंजीवाद आज जिस संकट से गुजर रहा है उसका विकल्प मार्क्स की विचारधारा और दर्शन के अलावा अन्य कुछ नहीं।'' कार्ल मार्क्स की 206वीं जन्म जयन्ती और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की 175वीं जयंती के अवसर पर 5 मई को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पश्चिम बंगाल राज्य परिषद और कालांतर ने भूपेश भवन के लाहिरी–मुखर्जी आडिटोरियम में एक विचार–विमर्श मीटिंग का आयोजन किया जिसमें मार्क्सवादी दार्शनिक प्रो. सोरिन भट्टाचार्य ने यह बात कही।

मीटिंग की अध्यक्षता प्रख्यात लेखक कपिल कृष्ण ठाकुर ने की। उन्होंने पुष्प गुच्छ भेंटकर मुख्य वक्ता का स्वागत किया और पार्टी के राज्य सचिव स्वप्न बनर्जी ने उन्हें एक स्मृति चिन्ह भेंट किया।

मीटिंग का प्रारम्भ करते हुए स्वप्न बनर्जी ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की 175वीं जयंती को मनाते हुए मार्क्सवाद की प्रासंगिकता को प्रोत्साहन देकर सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन जिला स्तर पर भी किए जाएंगे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मार्क्सवाद को सभी देशों में एक तरह से लागू किया जाये, यह आवश्यक नहीं। हरेक देश अपनी संस्कृति, जीवन के तरीके और सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक मुद्दों के आधार पर मार्क्सवाद को लागू करेगा। मार्क्सवाद और मार्क्सवादी दर्शन की अपनी सीमाएं हैं परन्तु पूंजीवाद के खिलाफ लड़ने के लिए वही एकमात्र हथियार है। अतः जरूरी है कि इस हथियार को सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाये। जिस प्रकार मार्क्सवादी सिद्धांत पर विचार–विमर्श आवश्यक है ठीक उसी तरह मार्क्सवाद को किस तरह लागू किया जाये उस पर भी विचार–विमर्श जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर पार्टी नेता और कार्यकर्ता कन्फ्यूज हो सकते हैं क्योंकि सिद्धांतवेत्ता सिद्धांत को अधिक महत्व देते हैं। अतः मार्क्सवादी दर्शन और उसको लागू करने के तरीके दोनों ही बातें बराबर महत्व रखती हैं।

175 साल पहले जब कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा गया था, उसके बाद से दुनिया में बहुत बड़े–बड़े परिवर्तन हो चुके हैं। पर उससे घोषणा पत्र की बुनियादी बातों का खंडन नहीं होता। वस्तुतः विश्व पूंजीवाद आज वास्तव में जिस तरह है वह 1848 में पूंजीवाद जिस तरह का था उसके मुकाबले पूंजीवाद के ''अमूर्त'' मॉडल के काफी निकट है जिसे घोषणा पत्र के पहले हिस्से में व्यक्त किया गया है। उस समय उत्पादन की पूंजीवादी व्यवस्था असल में केवल ब्रिटेन में ही हावी थी। ब्रिटेन से बाहर दुनिया के बाकी देशों में बड़े यंत्रीकृत औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले वेतनभोगी मजदूरों का वर्ग आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा था। दुनिया के अधिकांश लोग किसान थे जिनका पूर्व–पूंजीवादी भूस्वामी शोषण करते थे और इन भूस्वामियों के मुखिया अत्याचारी एवं निरकुंश वंशानुगत राजा हुआ करते थे। आज मजदूरी और वेतन पर निर्भर करने वाले वे लोग जो अपनी श्रमशक्ति को बेचने को मजबूर हैं, यूरोप, उत्तर अमरीका, जापान और आस्ट्रेलिया जैसे विकसित पूंजीवादी देशों में आर्थिक तौर पर सक्रिय आबादी के लगभग 80 प्रतिशत हैं। विश्व स्तर पर शहरी और ग्रामीण मजदूरी कमाने वाले लोग और उनके आश्रित परिवार मिलकर आज विश्व की आबादी का अधिकांश हिस्सा हैं।

सुबोध दत्ता

इस अवसर के मुख्य वक्ता प्रो. सोरिन भट्टाचार्य ने मार्क्सवाद के सिद्धांत और 1917 की रूसी क्रांति में मार्क्सवाद का विश्लेषण करते हुए मजदूर वर्ग के शोषण और दुनिया के विभिन्न देशों में पूंजीवाद के हमले के खिलाफ मार्क्सवाद और उसकी विचारधारा को लागू करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सोवियत संघ का यद्यपि पतन हो चुका है परन्तु मार्क्सवाद और उसके आदर्श आज भी कायम हैं। मार्क्सवाद आज भी प्रासंगिक है और वह मानव सभ्यता के विकास के अनुकूल है।

उनके वक्तव्य के बाद श्रोताओं ने उनसे अनेक प्रश्न पूछे जिसका उन्होंने संतोषणपूर्ण उत्तर दिया।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पश्चिम बंगाल की तमाम राज्य परिषदों ने कार्ल मार्क्स की 206वीं जयंती मनाई। इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि आधुनिक दुनिया में मार्क्सवाद और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र अधिकाधिक प्रासंगिक बना है। अपने जारी संकट से बचने के लिए पूंजीवाद क्रोनी पूंजीवाद में बदल गया है। हमारे देश में क्रोनी पूंजीवाद की कुत्ता–बिल्ली दौड़ चल रही है। हमारे राज्य में भी यह देखा जा सकता है।

दुनिया के इतिहास में अनेक दार्शनिकों ने समाज में असमानता के बारे में कहा है। परन्तु यह मार्क्स ही थे जिन्होंने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में बताया कि इस स्थिति को बदला जा सकता है।

5 मई को कोलकाता में वाम मोर्चा ने सुरेन्द्रनाथ पार्क में स्थित मार्क्स और एंगेल्स की प्रतिमाओं को माल्यार्पण किया। इस अवसर पर वाममोर्चा के चेयरमैन विमान बसु, भाकपा राज्य सचिव स्वप्न बनर्जी के अलावा सूर्यकान्त मिश्रा, मनोज भट्टाचार्य, नरेन चटर्जी, प्रबीर देव, गौतम राय, कल्याण बनर्जी आदि उपस्थित थे। भूपेश भवन में स्वप्न बनर्जी और राज्य सचिवमंडल के सदस्यों ने कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स की प्रतिमाओं को माल्यार्पण किया।

महिला सशक्तिकरण के बावजूद : बढ़ती असुरक्षा चिंताजनक

पिछले दिनों हमने होली के रंगों के साथ विश्व महिला दिवस मनाया उधर बीबीसी की एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि हिन्दुस्तानी शहरों में लड़कियों और महिलाओं का घर से निकलना लडकों और आदमियों के मुकाबले कितना कम होता है। इनमें अलग–अलग प्रदेशों में अलग–अलग तबकों की लड़कियां और महिलाएं हैं, और उनमें से अधिकतर का यह मानना है कि वे सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षित महसूस नहीं करतीं। यकीनन महिला सुरक्षा एक सामाजिक मसला है, इसे जल्द से जल्द सुलझाने की जरुरत है। महिलाएं देश की लगभग आधी जनसंख्या है जो शारीरिक, मानसिक, और सामाजिक रूप से पीड़ित है। यह देश के विकास तथा तरक्की में बाधा बन रहा है।

महिला सुरक्षा के लिए यूं तो कानून में बहुत सी व्यवस्थाएं हैं और सतत उनकी सुरक्षा के तहत नए सिरे से कोशिशें भी लगातार होती रहती हैं। बहुचर्चित निर्भया कांड के बाद आए कानून से तो ऐसा लग रहा था कि अब तमाम घटनाओं पर विराम लग जाएगा किंतु परिणामों में कोई बदलाव परिलक्षित नहीं हुआ। अपराधी तत्वों ने

सुसंस्कृति परिहार

अब यौन हिंसा का घृणित स्वरुप ले लिया। अब बलत्कृत पीड़िता को मौत के घाट उतार देना आम बात हो गई है। आजकल सारे सबूत खत्म कर देने की घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं अकेली महिला जहां एक मर्द से निपटने तैयार होने की कोशिश करने लगी तो बलात्कार में सामूहिकता बढ़ने लगी। तू डाल डाल मैं पात पात। आज सभी कानून फिसड्डी साबित हो रहे हैं।

देश में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध चिंता का विषय हैं. एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि बलात्कार के मामले 12 प्रतिशत तक बढ़ गये। बीते 10 वर्षों में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 75 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज हुई है।

हाल ही के दिल्ली का श्रद्धा वाल्कर हत्याकांड हो या झारखंड का रूबिका पहाड़िन हत्याकांड, हाल–फिलहाल ऐसे कई मामले सामने आये हैं जो बताते हैं कि देश में महिलाओं के खिलाफ न केवल अपराध बढ़े हैं बल्कि क्रूरता की वारदातें भी बढ़ी हैं। दिल्ली के कंझावला में ऐसी घटना घटी, जिसने नृशंसता की सारी हदें पार कर दीं। काम खत्म कर देर रात घर लौट रही अंजलि की स्कूटी पलट गयी और वह एक कार में फंस गयी। पर कार में बैठे लड़के पीड़िता की मदद करने की बजाय उसे किसी निर्जीव वस्तु की तरह कई किलोमीटर तक घसीटते रहे। महिलाओं के साथ क्रूरता की हद पार करने वाली यह कोई पहली घटना नहीं है।

एकं रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 30 मिनट में एक रेप होता है... माफ कीजिये, होता था.. 2014 तक।

शेष पेज 14 पर...

महिला सशक्तिकरण के बावजूद : बढ़ती...

पेज 13 से जारी...

अब तो भारत तरक्की कर चुका है अतः 2021 तक भारत में हर 16 मिनट पर एक रेप रिपोर्ट होता रहा जो वारदात सामने नहीं आ पाती उनकी संख्या का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सकता क्योंकि आज भी महिला अपने परिवार और समाज की ही बात मानती है क्योंकि नजदीकी परिवार जन, जान पहचान वाले अधिकतर इस दुष्कर्म में शामिल होते हैं उनसे पंगा लेना आसान नहीं होता। जो बगावत कर आगे आती हैं उनकी स्थिति बहुत बदतर हो जाती है वे कहीं की नहीं रहती। जिन्हें सरकारी संरक्षण मिलता है वह भी बिना मोल चुकाए कम ही मिलता है। महिला संरक्षण गृहों को अय्याशी का अड्डा बनाने की अनेक घटनाएं इतनी शर्मनाक हैं जहां संरक्षिका खुद बा खुद इस केंद्र का इस्तेमाल अधिकारियों और क्षेत्रीय नेताओं को संतुष्ट करने में करती रही।

ऐसे हालात में पीड़िता क्या करेगी वह घर पर रहना ही पसंद करेंगी भले उसे कितना दुराचार सहना पड़े। महिलाएं हर मुकाम पर अपना परचम लहरा रहीं हैं किंतु कितनी? जो घर से बाहर निकल रहीं उन्हें समाज की स्वीकार्यता कितनी और कैसी है। यह किसी से छिपा नहीं दिल्ली से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के करनाल जिले की देवीपुर ग्राम पंचायत में आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी लड़कियों को कॉलेज जाना नसीब नहीं हुआ था। नैना ने बताया कि जब उसके पिता ने मना किया तो उसने कहा, 'मैं भी जिद पर अड़ गई थी कि मैं पढ़ूंगी तो बस पढ़ूंगी। मैंने कह दिया कि अगर मैं कुछ गलत करूं तो आप मेरी नाड़ (गर्दन) काट देना। वह पढ़ी और आज पंचायत में लड़कियां पढ़ने लगी है। सच है, आमतौर पर जो जिद्दी महिलाएं हैं वे अपनी दम खम के साथ ही मौजूद हैं। ऐसी हिम्मत वालियों की संख्या बढ़ने पर ही परिवर्तन की गुंजाइश बनती है।

जो महिलाएं इसका एकमात्र इलाज ये मानती हैं कि वे घर में रहें बाहर ना निकले। यह मनुवादी सोच है। आज की सरकार की भी यही सोच परिलक्षित हो रही है। तो क्या घर मुफीद हैं। नहीं ना। तब तो घर से निकलना ही उचित होगा। जो डर गया वो मर गया। काश! हमारे समाज के मुखियाओं ने ईमानदारी से महिलाओं के ईमान की रक्षा घर से ही की होती तो बाहर का माहौल इतना घृणित नहीं होता। दुर्भाग्य तो यह रहा कि रक्षक ही गांव से लेकर शहर तक भक्षक बना बैठा है। महिलाओं की तरक्की के बाद भी आज वह सुरक्षित नहीं है। अब सरकार ही जब खुलकर बलात्कारियों का सम्मान कर रही हो तो किसके आगे महिला सुरक्षा की बीन बजाई जाए।

तब एक अपेक्षा महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं से ही की जा सकती है यदि महिलाएं सजगता से बिना अपना पराया किए हर जगह हर समय अपनी नजर पैनी रखें तथा एकजुटता से ऐसे लोगों की खबर ले भले वह व्यक्ति घर का हो, दफ्तर का हो, सड़क छाप हो या मंत्री, संत्री हो उसका डटकर प्रतिरोध हो उसका सामाजिक बहिष्कार हो तो शायद कुछ बदलाव आए। निडरता, जागरूकता, सक्रियता और सभी के आत्मबल से यूं कहें कि जिद से इस मसले को हल कर सकते हैं। इसमें पुरुषों की भागीदारी भी सुनिश्चित करें उनके सहयोग से ही सामाजिक सोच में बदलाव आएगा क्योंकि हम आज भी कथित पितृसत्तात्मक सत्ता के अधीन हैं उनके सहयोग को देख ही, अपराध करने वालों के हौसले पस्त होंगे। इसका मतलब यह नहीं अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी जाए। वह तो पुरातन नियमों में है ही लेकिन जब खेत ही बाड़ खाने लगे तो महिलाओं की यह अहम जिम्मेदारी बनती है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु जितने कढानून बने हैं उनका अमल घर से शुरू कराया जाए।हर घर में यह मुहिम चले और फिर आगे बढ़ा जाए।

कुछ लोग अपराधियों को सार्वजनिक तौर पर दंडित करने के पक्षधर हैं उनका मानना है कि समाजिक सुधार हेतु यह जरूरी है। पिछले दिनों महिला दिवस के दिन मध्यप्रदेश के एक जिला दमोह में एक बुजुर्ग बलात्कारी के शासकीय अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया खास बात ये रही कि बलात्कारी के घर पर जेसीबी चलाने वाली पूरी टीम महिला पुलिस की थी जिनको हौसला पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने दिया। यह अनूठी घटना थी जिसकी कल्पना कभी अपराधी ने नहीं की होगी। नारी अपमान का प्रतिशोध नारियों ने लिया। यह जरूरी है। बुलडोजर संस्कृति अच्छी नहीं कही जा सकती पर अपराधी के घृणित कार्य और शासकीय कई एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा दोनों बड़े गुनाहों के लिए यह सजा छोटी कही जायेगी। यह महिला दिवस हमेशा यादों में रहेगा। महिलाओं को ऊर्जा देता रहेगा।

कुल मिलाकर कुछ कदम तुम चलो कुछ कदम हम चलें दोनों के मेलजोल और कानूनों के तहत जल्द और सख्त कार्रवाई का असर निश्चित तौर पर असरकारक होगा लेकिन महिलाओं के बिना जागे सबेरा नहीं होगा।

पी.पी.एच. पब्लिकेशन

पुस्तक	लेखक	मूल्य
1. भारतीय दर्शन में क्या जीवंत है और क्या मृत	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	500.00
2. बाल जीवनी माला	कॉपरर्निकस	12.00
3. बाल जीवनी माला	निराला	12.00
4. बाल जीवनी माला	रामानुज	12.00
5. बाल जीवनी माला	मेंडलिफ	50.00
6. बाल जीवनी माला	प्रेमचंद	50.00
7. बाल जीवनी माला	सी.वी. रमन	50.00
8. बाल जीवनी माला	आइजक न्यूटन	50.00
9. बाल जीवनी माला	लुईपाश्चर	50.00
10. बाल जीवनी माला	जगदीश चन्द्र बसु	50.00
11. फैज अहमद फैज–शख्स और शायर	शकील सिद्दीकी	80.00
12. फांसी के तख्ते से	जूलियस फ्यूचिक	100.00
13. कितने दोबाटिक सिंह भारत विभाजन की दस कहानियां	भूमिका: भीष्म साहनी	60.00
14. मार्क्सवाद क्या है?	एमिल बर्न्स	40.00
15. फैज़ अहमद फ़ैज़: प्रतिनिधि कविताएं	संप श्री अली जावेद	60.00
16. दर्शन की दरिद्रता	कार्ल मार्क्स	125.00
17. हिन्दू पहचान की खोज	डी.एन. झा	100.00
18. प्राचीन भारत में भौतिकवाद	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	200.00
19. 'जब मैंने जाति छिपायी थी' तथा अन्य कहानियां	बाबुराव बागुल	200.00
20. बाल–हृदय की गहराइयां		
माँ–बाप और शिक्षकों से अंतरंग बातचीत	वसीली सुखोम्लीन्स्की	350.00
21. चीन की पुरस्कृत कहानियां भाग–1, 2		185.00
22. बच्चों सुनो कहानी	लेव तोलस्तोय	175.00
23. जहां चाह वहां राह–उज़बेक लोक कथाएं		360.00
24. हीरेमोती–सोवियत भूमि की जातियों की लीक कथाएं		300.00
25. दास्तान–ए–नसरूदीन	लियोनिद सोलोवयेव	370.00
26. लेनिन–क्रुप्स्काया (संस्मरण)	क्रुप्स्काया	485.00
27. साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की चरम अवस्था	लेनिन	65.00
28. बिसात–ए–रक्स	मख़दूम	100.00
29. भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण	भगवत शरण उपाध्याय	100.00
30. राहुल निबंधावली (साहित्य)	राहुल सांकृत्यायन	90.00
31. मैं नास्तिक क्यों हूं	भगत सिंह	75.00
32. विवेकानंद सामाजिक–राजनीतिक विचार	विनोय के. राय	75.00
33. रामराज्य और मार्क्सवाद	राहुल सांकृत्यायन	60.00
34. कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र	मार्क्स एंगेल्स	50.00
35. भगत सिंह की राह पर	ए.बी. बर्धन	15.00
36. माटी का लाल–कृति पुरूष कामरेड दुर्जन भाई	डा. रामचन्द्र	110.00
37. क्या करें	लेनिन	80.00
38. मेक इन इंडिया –आंखों में धूल	सी. मुरलीधर, एम. सत्यानन्द	30.00
39. भारतीय इतिहास में जाति और मुद्रा	इरफान हबीब	40.00
40. वर्ग जाति आरक्षण और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष	ए.बी. बर्धन	60.00

आर्डर भेजें:
पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड
5–ई, रानी झांसी मार्ग
नई दिल्ली–110055
दूरभाष: 011–23523349, 23529823
ईमेल: pph5e1947@gmail.com
https//pphbooks.net

दिल्ली के शोरूम
जी–18, आउटर सर्कल, कनाट प्लेस
नई दिल्ली–110001, फोन: 23324064
पीपीएच बुकशॉप, जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी के पास,
नई दिल्ली–110 067, फोन: 65447645
पीपीएच शॉप, अजय भवन
15, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त मार्ग, नई दिल्ली–2

नोट: आप भेज सकते हैं:
चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक मनिआर्डर ''पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड'' के पक्ष में
बैंक विवरण:
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट: 32074674284, आई.एफ.सी. कोड: SBIN0009371

मोदी सरकार से प्रेस की आजादी को...

पेज 3 से जारी...

के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई और केवल 1 आरोपी को ही अदालत ने दोषी पाया। वहीं 2015 में इस कानून के तहत 73 गिरफ्तारियां हुई और 13 के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई लेकिन इनमें से एक को भी अदालत में दोषी नहीं साबित किया जा सका। इसी तरह 2014 में 58 लोगों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया लेकिन सिर्फ 16 के खिलाफ ही चार्जशीट दायर हुई और उनमें से भी केवल 1 को ही अदालत ने दोषी माना।

हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर और आरएफ नरीमन की पीठ ने 24 अप्रैल, 2015 को जनहित याचिका पर सुनवाई कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आधारभूत मूल्य घोषित करते हुए सूचना तकनीक कानून की धारा 66–ए को खत्म करने का निर्देश दिया था। चूंकि बड़ी संख्या में गिरफ्तारी इसी कानून के तहत की गई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने दलील थी कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच संतुलन कायम करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकारें खुद तय करें कि यह काम कैसे किया जाए। लेकिन कानून का भय दिखाकर बोलने की आजादी पर प्रतिबंध लगाना संविधान के अनुच्छेद 19–(1) के तहत प्रदत्त वैचारिक अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के बाद भी सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर राज्य सरकारों द्वारा गिरफ्तारी का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। जबकि देश की तमाम अदालतें इसे लेकर सरकारों को चेतावनी देती रही हैं। इसी साल की शुरुआत में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। महज इसके लिए किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। अब केन्द्र सरकार सोशल मीड़िया पर कानून बनाकर इसकी लगाम कसने की तैयारी कर रही है।

सोशल मीड़िया पर मोदी सरकार की नकेलबंदी

25 फरवरी को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 को अधिसूचित किया। मंत्रालय अधिसूचना में कहता है कि ऐसा डिजिटल मीडिया से संबंधित उपयोगकर्ताओं की पारदर्शिता, जवाबदेही और अधिकारों की कमी के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच और जनता और हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद किया गया। हालांकि सरकार के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है।

इन नए नियमों के अनुसार सोशल मीडिया सहित सभी मध्यस्थों को ड्यू डिलिजेंस या उचित सावधानी का पालन करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें कानून के द्वारा दी गई सुरक्षाएं नहीं मिलेंगी। साथ ही ये नियम मध्यस्थों को शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने को कहते हैं और उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से महिला उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मध्यस्थ पर डालते हैं। इन नियमों के अनुसार गैर–कानूनी जानकारी को हटाने की जिम्मेदारी भी मध्यस्थों की होगी और उन्हें उपयोगकर्ताओं को सुनने का अवसर देना होगा और एक स्वैच्छिक उपयोगकर्ता सत्यापन तंत्र की स्थापना करनी होगी। जिन सोशल मीडिया मध्यस्थों के 50 लाख से ज्यादा उपभोक्ता हैं उनके लिए सरकार ने कहा कि उन्हें एक मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी जो अधिनियम और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। साथ ही इन बड़े मध्यस्थों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ चौबीसों घंटे समन्वय के लिए एक नोडल संपर्क अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी जो शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत कार्यों को करेगा। इन पदों पर उन्हीं लोगों की नियुक्ति होगी जो भारत के निवासी हों. साथ ही प्राप्त शिकायतों के विवरण और शिकायतों पर की गई कार्रवाई के साथ–साथ इन सोशल मीडिया मध्यस्थों द्वारा सक्रिय रूप से हटाई गई सामग्री के विवरण का उल्लेख करते हुए एक मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी।

इस पूरे घटनाक्रम पर साइबर कानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल का कहना है कि सरकार इस कानून के माध्यम से अब पेंच कसना शुरू कर देगी। वे कहते हैं कि इन नियमों ने कंपनियों के सिर पर एक तलवार लटका दी है और इस तलवार का इस्तेमाल कहां कंपनियों के खिलाफ किया जायेगा उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उनके अनुसार इन नियमों के माध्यम से सरकार मध्यस्थों और सेवा प्रदाताओं पर अपना नियंत्रण मजबूत करती है और उन्हें कुछ चीजें करने के लिए विवश करती है और अगर वे न करें तो उन्हें जेल भेजा सकता है। उनके अनुसार इसका कारण ये है कि जो नियम आये हैं उन्होंने पूरी तरह लीगल फ्रेमवर्क को बदल दिया है।

दुग्गल कहते हैं कि पहले ऐसा होता था कि सर्विस प्रोवाइडर से जानकारी माँगी जाती थी और अगर जानकारी नहीं मिलती थी तो बात आगे नहीं बढ़ती थी। नए नियमों के अनुसार अगर सर्विस प्रोवाइडर जानकारी नहीं देंगे तो उनके विरुद्ध क्रिमिनल कार्रवाई हो सकती है और उनको आईटी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए दंडित किया जा सकता है।

सरकार के हालिया प्रस्ताव के मुताबिक किसी भी ऑनलाइन कन्टेंट को सच या झूठ घोषित करने की शक्तियां पीआईबी फैक्ट चेकिंग यूनिट के हाथ में दे दी जाएँगी। चिंता जताई जा रही है कि अगर ऐसा होता है तो सरकार का सोशल मीडिया पर नियंत्रण बढ़ने वाला है जिसका असर न्यूज मीडिया पर भी होगा।

हालांकि पीआईबी सरकार की नीतियों और कार्यों की जानकारी देने वाली सरकारी एजेंसी है और फैक्ट चेकिंग की व्यवस्था कभी भी पीआईबी के दायरे में नहीं आ सकती है। कई बार उसके द्वारा पेश तथ्यों पर भी सवाल उठे हैं। दुनिया भर में फैक्ट चेकर्स को प्रमाणित करने वाले इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क ने भी पीआईबी को फैक्ट–चेकर के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया है। सरकार ने समस्या का समाधान करने की अपेक्षा समस्या को और बढ़ा दिया है। मोदी सरकार की मंशा एकदम साफ है, वह सोशल मीड़िया की स्वतंत्रता को खत्म करना और उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। चूंकि सोशल मीड़िया कोई एक ऐसी कंपनी अथवा घराना नहीं है जिसे खरीदा जा सके। इसीलिए उस पर नियंत्रण के लिए कानून लाया जा रहा है। हालांकि कई राज्यों ने इस पर आपत्ति जतायी है और इसे चुनौती दी है। जिस पर इस अधिसूचना के कई हिस्सों पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। फिर भी पूरा मामला अभी तक भी न्यायपालिका के विचाराधीन है।

प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले का गुजरात मॉडल

दरअसल, देश में बेशक प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला 2014 के बाद तेज हुआ हो परंतु इसका प्रयोग उससे पहले से ही गुजरात में जारी था। गुजरात सरकार द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता का गला घोंटने के प्रयास के कई उदाहरण सामने हैं। कैसे प्रेस की स्वतंत्रता का गला गुजरात में राज्य मशीनरी विशेषकर पुलिस के सहारे घोटा जा रहा था उसका मॉडल हम यदि हम 2002 की घटना को लें तो इस मॉडल को समझने में आसानी होगी। रिपोर्टर्स विदाउट बार्डर्स ने भी इस घटना को रिपोर्ट किया है। 7 अप्रैल 2002 को पुलिस अधिकारियों ने अहमदाबाद स्थित गांधी आश्रम के समक्ष आयोजित दो शांति प्रदर्शनों और उसको कवर कर रहे पत्रकारों और मीड़ियकर्मियों पर भाजपा के युवा संगठन, गुजरात युवा मोर्चा के सदस्यों द्वारा हमला किया गया और उन पर दमनात्मक कार्रवाई की। जैसे ही युवा मोर्चा के सदस्यों ने गुंडागर्दी प्रारंभ की, पुलिस के डिप्टी कमिश्नर वी. एम. परघी ने निजी टेलीविजन चैनल एनडीटीवी के कैमरामैन प्रणव जोशी को अपना कैमरा बंद करने के लिए कहा। जब जोशी ने यह जानना चाहा कि उन्हें अपना कैमरा क्यों बंद करना चाहिए तो उनके सिर पर जोर से कोई चीज मारी गई, जिसके बाद वे जमीन पर गिर गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इसके बाद पुलिस पत्रकारों पर टूट पड़ी और उन्हें बंदूकें दिखाकर डराया, धमकाया गया। यह गैर–कानूनी कार्यवाही लगभग 10 मिनट तक चलती रही, जब तक कि पुलिस अधीक्षक शिवानंद झा ने पुलिस जवानों को मारपीट बंद करने के लिए नहीं कहा। इस पुलिस हमले में 10 पत्रकार और विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों के फोटोग्राफर गंभीर रूप से घायल हो गए और उनमें से एक को इंटेन्सिव केयर यूनिट (आईसीयू) में भर्ती कराना पड़ा। इसके तुरंत बाद, मीडियाकर्मियों ने पूरी घटना को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करायी।

परंतु उसी रात गुजरात के गृहमंत्री ने एक बयान जारी कर इस बात से इंकार किया कि पुलिसकर्मियों ने पत्रकारों पर हमला किया है। परंतु कुछ घंटों बाद एक और आधिकारिक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि मामले की जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त किया जायेगा। यह कहा गया कि आयोग अपनी रपट तीन हफ्तों के अंदर देगा। 8 अप्रैल को गुजरात सरकार ने यह घोषित किया कि शिवानंद झा और वी. एम. परघी को स्थानांतरित किया जा रहा है और मामले की आपराधिक प्रकरण के रूप में जांच की जाएगी। इस 'आपराधिक जांच' का आज तक कोई नतीजा सामने आया हो ऐसी कोई खबर अभी तक नहीं है। परंतु इस बीच, 2002 में ही वी. एम. परघी को डिप्टी कमिश्नर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। मोदी के केन्द्र की सत्ता में आने के बाद 15 अगस्त 2014 को वे पुलिस, ट्रेफिक और आपराधिक मामलों के ज्वाईट कमिश्नर बनाये गये और उन्हें राष्ट्रपति के पुलिस पदक से भी नवाजा गया। जिस दूसरे पुलिस अधिकारी ने सन् 2002 के पत्रकारों पर हमले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसे 12 सितंबर 2011 को गृह सचिव नियुक्त कर दिया गया और अक्टूबर 2013 में अहमदाबाद का पुलिस कमिश्नर बना दिया गया।

नाजी ब्राउन शर्ट गुंडों की तरह इन तथाकथित हिन्दू राष्ट्रवाद के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर कथित रूप से अपमानजनक या असम्मानजनक टिप्पणियां करने वालों को सबक सिखाने के लिए उन पर हमले किए और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसी तरह की घटना पुणे में एक घटी। जिसमें हिन्दू अतिवादियों ने एक निर्दोष युवा मुस्लिम आईटी कर्मी को इसलिए मार डाला क्योंकि वे फेसबुक पर एक पोस्ट में एक हिन्दू योद्धा और एक हिन्दू राजनैतिक नेता की तस्वीरें लगाए जाने से अपमानित महसूस कर रहे थे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल पत्रकारों पर हमले करने और उन्हें धमकाने के लिए किया जा रहा है। मोदी की जरा सी भी निंदा बर्दाश्त नहीं की जाती है। केरल में नौ छात्रों को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने अपने कालेज की पत्रिका में एक क्रासवर्ड पहेली का प्रकाशन किया, जिसमें मोदी के नाम का इस्तेमाल किया था। यह इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने अन्य पार्टियों के नेताओं पर भी निशाना साधा था।

मोदी या भाजपा की आलोचना करने वालों के प्रति शत्रुता का भाव आम हो चला है। जिसके खिलाफ देश की कई जानीमानी हस्तियों (जिनमें सामाजिक कार्यकर्ता अरूणा रॉय, इतिहासविद् रोमिला थापर व अर्थशास्त्री जयती घोष व जीन ड्रेस शामिल थे) ने एक संयुक्त बयान जारी कर प्रधानमंत्री की ऐसे लोगों की अभियक्ति की आजादी पर हो रहे हमलों पर चुप्पी पर प्रश्न उठाया था। बयान जारी करने वालों ने प्रधानमंत्री से यह अपील की कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करें और 'असहिष्णुता और भय के भय के उस वातावरण को खत्म करने का प्रयास करें जो हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुका है।

मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक 14 – 20 मई, 2023

Delhi Postal Regd. No. DL(C)-01/1277/2021-23
Licenced to Post without Pre-payment. U(C)-102/2021-23
(R.N.I. No. 20196/70) Posted in LPC, DRMS, Friday & Saturday

प्रकाशन तिथि: 12.5.2023

कार्ल मार्क्स जयंती मनायी गयी

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की इकाइयों ने 5 मई, 2023 को पूरे देश में बड़े उत्साह और जोश के साथ कार्ल मार्क्स की 205वीं जयंती मनाई। पार्टी महासचिव डी राजा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय, अजय भवन में कार्ल मार्क्स के चित्र पर माल्यार्पण किया। इसके बाद पार्टी के नेताओं और कामरेडों ने वहां इकट्ठा होकर कार्ल मार्क्स के चित्र पर फूल चढ़ाए।

कार्ल मार्क्स को भावपूर्ण श्रद्धांजलि पेश करते हुए डी राजा ने कहा कि महान दार्शनिक और समाज सुधारक को आदर देने का सबसे बेहतर तरीका वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना और शोषण का अंत करने के लिए संघर्ष को तेज करना होगा।

उन्होंने रेखांकित किया कि हमारा देश एक कठिन समय से गुजर रहा जबकि दक्षिणपंथी फासीवादी ताकतें बड़े संघर्षो से कमाई हमारी आजादी को बर्बाद करने पर तुले हैं, संविधान को कमजोर कर रही हैं और हमारे जनवादी ढ़ांचे को नुकसान पहुंचा रही हैं।

पटना

सर्वहारा के महान चिंतक कार्ल मार्क्स की 205वीं जयंती केदारदास श्रम व समाज अध्ययन संस्थान द्वारा मनायी गयी। विषय था 'धर्म के संबंध में मार्क्स का दृष्टिकोण और शासक वर्ग'। जयंती कार्यक्रम में पटना शहर के बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, रंगकर्मी, ट्रेड यूनियन तथा वामपंथी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। स्वागत वक्तव्य केदारदास श्रम व समाज अध्ययन संस्थान के सचिव अजय कुमार ने रखा।

प्रारम्भिक संबोधन में अशोक कुमार सिन्हा ने कहा 'धर्म प्राकृतिक शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए कई किस्म के त्याग की बात करता है जबकि मार्क्सवादी लोग प्राकृतिक शक्तियों को कार्य–कारण संबंध के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ प्रचार करने से, जो धार्मिक भावनाएं, लोगों के दिमाग में हैं, उनको दूर नहीं किया जा सकता। जो धार्मिक लोग हैं उनको सामाजिक–राजनीतिक संघर्षो में कैसे खींचा जाये सबसे आवश्यक यही है। यदि हम आम लोगों के प्रश्नों पर उन्हें ले आएं जब वे संघर्ष की पातों वे शामिल हो जाएँ तब उनसे धर्म की नकारात्मक भूमिका की चर्चा करें।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मा) के नेता सर्वोदय शर्मा ने कहा कि धर्म के संबंध में मार्क्स की प्रसिद्ध उक्ति 'धर्म जनता के लिए अफीम है' को बहुत ज्यादा गलत समझा गया है। इस पंक्ति को हमेशा संदर्भ से काटकर देखा गया है। दरअसल कम्युनिस्ट लोगों में भी बहुत भ्रम की स्थिति है। धर्म को मार्क्सवादियों ने प्रकृति के सबंधों के संदर्भ में देखा गया। जैसे–जैसे विज्ञान का विकास हुआ तब बहुत सारी चीजें समझी जा सकी। लेकिन कुछ चीजों को अब तक नहीं समझा जा सका है। आदिम युग से आजतक सरपल्स की अवधारणा आई। मानव समाज के इस स्टेज में धर्म को आदिम युग से आजतक शोषण के औजार के रूप में देखा गया। यह मुट्ठी भर लोगों के वर्चस्व के रूप में काम करता है।

अवकाशप्राप्त प्रशासनिक पदाधिकारी तथा उपन्यासकार व्यास जी मिश्रा ने 'पुराण', 'ओल्ड टेस्टामेन्ट, 'कुरानशरीफ' आदि का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले माना जाता था कि ईश्वर ने अचानक फैसला किया और धरती का निर्माण कर दिया। ऐसी –ऐसी कहानियाँ इन ग्रंथों में वर्णित हैं जिसपर विश्वास करना कठिन होता है लेकिन आज भी उन कहानियों के पात्रों के नाम पर लोग अपने बाल– बच्चों के नाम रखते हैं। जब मैंने पहली बार अमेरिका की यात्रा की तो पृथ्वी के

हमारे विशेष संवाददाता द्वारा

एक ओर अंधेरा तो एक ओर उजाला रहता है। इस बात को इसे साइंस से आधार पर समझा जबकि धर्मग्रंथों में इस बात को रहस्यमय ढंग से बताया गया है। 296 वर्षो तक क्रूसेड चलता रहा है ताकि जेरुसलेम पर कैसे कब्जा किया जाये। यदि धर्म का वह पक्ष नफरत नहीं फैलाता तो उससे कोई दिक्कत नहीं। धर्म सिर्फ व्यक्तिगत आस्था की चीज रहें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि ईश्वर ने पृथ्वी को बनाया है तो एक दूसरे से नफरत की बात नहीं होनी चाहिए। कुरान जब आया तब अरब के देशों में बदअमनी फैली थी कोई सेन्ट्रल पावर नहीं थी। सम्प्रदायवाद से लड़ने का तरीका धर्म को गाली देना नहीं है।

सभा को सामजिक कार्यकर्ता अनिल कुमार राय, पटना विश्वदयालय में लोक प्रशासन के आध्यापक सुधीर कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता उदयन, ट्रेड यूनियन नेता डीपी यादव, गोपाल शर्मा, चंद्रबिन्द सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में सुमंत, अनीश अंकुर, रविकिशन, एटक महासचिव गजनफर नवाब, रामलला सिंह, इन्द्रनाथ झा, उमा कुमार, मंगल पासवान, बिट्टू भारद्वाज आदि शामिल थे।

इप्टा इंदौर

भारतीय जन नाट्य संघ (इप्टा) इंदौर ने 5 मई 2023 को कार्ल मार्क्स की जयंती को एक अभिनव अंदाज में मनाया। कार्ल मार्क्स और उनकी लिखी विश्व प्रसिद्ध किताब 'पूँजी' (जिसे जर्मन भाषा में 'दास कैपिटल' कहते हैं) के साथ ही कार्ल मार्क्स के विशिष्ट दर्शन मार्क्स की कुछ प्रमुख बातों का परिचय दिया। चूँकि 5 मई को ही बुद्ध पूर्णिमा भी थी और सोशल मीडिया पर इस आशय के लेख काफी कि बुद्ध बड़े या मार्क्स, तो इस मौके पर स्मृतिशेष इन्दु मेहता का एक पत्र जो 1980 के दशक में प्रकाशित हुआ था, पढ़कर सुनाया गया। पत्र में उन्होंने लिखा था कि बुद्ध और मार्क्स की तुलना करना गलत है। दोनों के समय में दो हजार बरस का अंतर है। बुद्ध और मार्क्स, दोनों के ही योगदान अपनी–अपनी तरह से अप्रतिम है। किसी एक को बड़ा बताने के लिए किसी दूसरे को छोटा करना जरूरी नहीं। विनीत ने यह भी बताया कि मार्क्स के पहले भी अनेक दार्शनिक हुए जिन्होंने दुनिया के के बारे में अपनी व्याख्यायाएं की हैं लेकिन मार्क्स वो पहले दार्शनिक थे जिन्होंने कहा था कि इसे बदला भी जा सकता है।

इसके उपरान्त चार्ली चैपलिन की प्रसिद्ध फिल्म 'मॉडर्न टाइम्स' का प्रोजेक्टर द्वारा प्रदर्शन किया गया।

विनीत तिवारी ने बताया कि यह फिल्म 1936 में चार्ली चौपलिन द्वारा बनायी गई थी और बेहद हास्यास्पद दृश्यों के जरिये चार्ली चौपलिन ने उस समय योरप में फैली भयानक बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी के बरअक्स उद्योगों में होने वाले मजदूरों के भीषण शोषण, अतिउत्पादन और मजदूरों के संघर्ष और जिजीविषा को फिल्म में प्रभावी तरह से अभिव्यक्त किया है। फिल्म का पहला दृश्य ही जानवरों की एक दिशा में भागती भीड़ का है जिसके तुरंत बाद उसी दिशा में भागते इंसानों की भीड़ दिखने लगती है। इस तकनीक को मोंटाज कहते हैं और इसके जरिये फिल्मकार बताता है कि मॉडर्न कहे जाने वाले इस समय में इंसान को जानवर तक घटा देने की कोशिशें चल रही हैं। निशा ने फिल्म को बेहद प्रभावी और कसी हुई बताया। रेहान और साजिद ने फिल्म में गरीबी और हास्य के चित्रण को बहुत असरदार बताया और अंत को उम्मीद से भरा बताया। अथर्व ने कहा कि फिल्म पूरी होने पर यह एक बहुत सकारात्मक असर छोड़ती है। तौफीक ने मजदूरों को खाना खिलाने के लिए अविष्कृत की गई मशीन के दृश्य को याद करते हुए बताया कि मजदूर को खुद के लिए कम से कम समय मिले और अधिकतर समय वो अपने आपको मालिक के मुनाफे की भेंट चढ़ाता रहे। फिल्म के हास्य में छिपे दुःख और करुणा के सन्देश की ओर ध्यान खींचा। अरविन्द जैन ने फिल्म को पूँजीवादी व्यवस्था में अनिवार्य तौर पर शामिल मुनाफे के संकट, जो अंततः इंसानियत को ही संकट में डाल देता है, पर एक तीखी टिप्पणी बताया। विजय दलाल ने कहा कि वर्षो पहले देखी गई इस फिल्म को देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह इतनी पुरानी फिल्म है क्योंकि आज भी हालात काफी मिलते–जुलते हैं। सारिका ने फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गरीबों के भीतर भी अमीरी को देखकर अमीर बनने की इच्छा जागती है, इस मानसिकता को भी यह फिल्म बखूबी बयान करती है। आदेश तिखे ने कहा कि फिल्म पूँजीवाद पर बेशक सवाल खड़े करती है लेकिन क्या समाजवाद में जो हुआ, वो सब ठीक था? जवाब में जया मेहता ने कहा कि समाजवादी देशों की प्राथमिकताओं में लोगों को मनुष्य होने के बुनियादी अधिकार देना था ताकि वे भूख से और दया से मुक्त होकर अपना सम्मानजनक जीवन जी सकें। इसमें बहुत हद तक वे देश कामयाब भी रहे। इसके उलट पूँजीवाद की तो संरचना में ही शोषण निहित है। समय को देखते हुए यह तय किया कि आगे जल्द ही इस पर विस्तार से बात होगी ।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से डी. राजा द्वारा BFL Infotech Ltd. (Media Division), C-9, Sector-3, Noida, Dist. Gautam Budh Nagar, UP द्वारा मुद्रित, अजय भवन, 15–कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली–110 002 से प्रकाशित। **संपादक**: रणबीर सिंह यादव फोन: 011–2323 0762 फैक्स 91–011–2323 5543.
e-mail: newagemukti@gmail.com, Layout: Udai Bhan Rajbhar.